नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 323
दि. 26.08.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बाढ़ पर गरमाई सूरत महानगरपालिका की आम बैठक, विपक्षी पार्षद रचना हिरपरा निलंबित; जलभराव से लेकर अधूरे प्रोजेक्ट तक उठे सवाल

सूरत। जुलाई में आई बाढ़ से सूरत शहर के कई हिस्सों में पैदा हुई गंभीर परिस्थितियों का मुद्दा मंगलवार को सूरत महानगरपालिका की आम बैठक में जमकर गूंजा। बाढ़ के दौरान कई इलाकों में घरों और दुकानों में पानी घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। घरेलू सामान, व्यापारिक सामग्री और अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचने के बाद राहत और मुआवजे को लेकर भी सवाल उठे थे। मंगलवार को हुई आम बैठक में यही मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया और चर्चा देखते ही देखते सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक में बदल गई। इसी दौरान विपक्षी पार्षद रचना हिरपरा को सदन से निलंबित कर दिया गया।

बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा के दौरान रचना हिरपरा ने शहर में जलभराव और बाढ़ की समस्या को लेकर भाजपा के लंबे समय से चले आ रहे शासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सूरत में वर्षों से बाढ़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है। हर साल मानसून के दौरान कई इलाकों में पानी भरता है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने सवाल किया कि इतने वर्षों के शासन के बाद भी शहर को बार-बार बाढ़ जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ रहा है।

रचना हिरपरा ने बाढ़ प्रभावित लोगों को मिलने वाले राहत और मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कई प्रभावित परिवारों को अपेक्षा के अनुरूप सहायता नहीं मिली है और कुछ लोग अब भी सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से प्रभावित लोगों की शिकायतों का समाधान करने और राहत व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

बहस उस समय और तीखी हो गई, जब रचना हिरपरा ने शहर की बाढ़ समस्या को लेकर लंबे समय से सत्ता में रहने वाली भाजपा पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि इतने वर्षों के शासन के बावजूद बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है, तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।

सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व पक्ष नेता अमित सिंह राजपूत ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने बाढ़ के दौरान प्रशासन और महानगरपालिका की ओर से किए गए राहत एवं बचाव कार्यों का बचाव किया। अमित राजपूत ने विपक्ष पर बाढ़ के मुद्दे को राजनीतिक रूप देने का आरोप लगाया। उन्होंने रचना हिरपरा पर तंज कसते हुए कहा कि बाढ़ के दौरान उन्हें मौके पर सक्रिय रूप से नहीं देखा गया और न ही उनकी कोई फोटो या रील सामने आई।

इस टिप्पणी के बाद सदन में माहौल और गर्म

हो गया। रचना हिरपरा ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि सरकार और प्रशासन ने बाढ़ के दौरान इतना अच्छा काम किया था, तो शहर को बार-बार बाढ़ का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो गई और सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।

बहस के बीच मेयर मायाबेन मावाणी ने रचना हिरपरा के व्यवहार को लेकर उन्हें सदन से निलंबित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद मार्शल उन्हें सदन से बाहर ले जाने के लिए आगे बढ़े। रचना हिरपरा ने इस कार्रवाई का विरोध किया और इसे तानाशाही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की ओर से जनहित के गंभीर मुद्दे उठाए जाने पर उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

दूसरी ओर, अमित सिंह राजपूत ने रचना हिरपरा के व्यवहार को देखते हुए उन्हें दो बैठकों के लिए निलंबित करने की मांग की। पूर्व मेयर दक्षेश मावाणी ने भी कहा कि जब तक रचना हिरपरा सदन में माफी नहीं मांगतीं, तब तक विरोध जारी रखा जाएगा। इस तरह बाढ़ और राहत-मुआवजे से शुरू हुई चर्चा आखिरकार पार्षद के निलंबन के विवाद में बदल गई।

बैठक में बाढ़ से बचाव के लिए किए गए और प्रस्तावित कार्यों की भी जानकारी दी गई। पार्षद दिनेश राजपुरोहित ने प्रशासन और सत्ता पक्ष की ओर से बाढ़ के दौरान किए गए बचाव और राहत कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सानिया, सरोली और कुंभारिया इलाकों में हर साल मानसून के दौरान खाड़ी का जलस्तर बढ़ने पर पानी भरने की समस्या पैदा होती है। इन क्षेत्रों में करीब 10 हजार घर हैं और औद्योगिक गतिविधियां भी होती हैं। ऐसे में बाढ़ का असर केवल आवासीय क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यापार और उद्योग पर भी पड़ता है। दिनेश राजपुरोहित के अनुसार, जब नाले का जलस्तर करीब 7.5 मीटर तक पहुंच जाता है, तब इन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से इस समस्या को लेकर मांग उठाई जा रही है। उन्होंने खाड़ी के आसपास सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की, ताकि पानी का फैलाव रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस काम को जल्द शुरू करने का आग्रह किया। बैठक में बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों का मुद्दा भी सामने आया। चर्चा के दौरान सूरत के व्यापारियों को मिली सहायता का उल्लेख किया गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के वसई, विरार और नालासोपारा जैसे क्षेत्रों में जलभराव से प्रभावित छोटे व्यापारियों की समस्याओं का भी संदर्भ दिया गया। मांग उठाई गई कि जिन व्यापारियों की दुकानों में पानी भरने से नुकसान हुआ है, उन्हें भी इसी तरह राहत और सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

बाढ़ और जलभराव से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा वीआईपी रोड स्थित खाटूश्याम मंदिर के आसपास का रहा। पार्षद रश्मि साबू ने बताया कि इस मानसून में वीआईपी रोड और खाटूश्याम मंदिर के आसपास भारी जलभराव हुआ था। इससे वहां रहने वाले लोगों के साथ-साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मालिकों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रश्मि साबू ने इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र में जल्द से जल्द स्टॉर्म लाइन बिछाने की मांग की। उन्होंने बताया कि लाइन बिछाने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है, लेकिन वास्तविक निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। उनका कहना था कि यदि स्टॉर्म लाइन का काम समय पर पूरा कर दिया जाए तो आने वाले मानसून में जलभराव की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका
आत्मसमर्पण से राहत की मांग खारिज

नई दिल्ली। 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराए गए पत्रकार और तहलका पत्रिका के संस्थापक एवं पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई होने तक आत्मसमर्पण से छूट देने की मांग की थी। अदालत ने तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा के मामले में दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। हालांकि उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को सुनवाई करेगा।

तेजपाल की ओर से अदालत में यह दलील दी गई थी कि उनकी आपराधिक अपील को पहले सूचीबद्ध कर सुनवाई के लिए लिया जाना चाहिए और जब तक उस पर सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक उन्हें आत्मसमर्पण करने से राहत दी जानी चाहिए। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि उचित परिस्थितियों में न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह आत्मसमर्पण की आवश्यकता को समाप्त कर सके और आरोपी के आत्मसमर्पण किए बिना भी उसकी आपराधिक अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर सकता है। तेजपाल की कानूनी टीम का कहना था कि यदि अपील पर जल्द सुनवाई होनी है तो आत्मसमर्पण की आवश्यकता पर भी उसी संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और आत्मसमर्पण से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही तेजपाल को निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।

गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेजपाल की याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत के सामने कहा कि आत्मसमर्पण से राहत देने के आवेदन पर मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के निष्कर्षों का भी हवाला दिया और कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है तथा तेजपाल को इसमें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय मुख्य सवाल तेजपाल की सजा पर अंतिम फैसला करना नहीं, बल्कि उनकी आत्मसमर्पण से छूट की मांग से जुड़ा था। अदालत ने फिलहाल इस मांग को खारिज कर दिया है। वहीं दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उनकी मुख्य अपील पर सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि आत्मसमर्पण का निर्देश फिलहाल लागू रहेगा, जबकि सजा और दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर आगे न्यायिक सुनवाई जारी रहेगी। तरुण तेजपाल का नाम भारतीय पत्रकारिता जगत में लंबे समय तक चर्चित रहा है। वे तहलका पत्रिका के संस्थापक और तत्कालीन प्रधान संपादक थे। वर्ष 2013 में उनकी एक जूनियर महिला सहकर्मी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। आरोप सामने आने के बाद तेजपाल ने संपादक के पद से छह महीने के लिए हटने की घोषणा की थी। उन्होंने उस समय कहा था कि ऐसा कदम मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उठाया जा रहा है।

केरल में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, भूस्खलन से सड़कें प्रभावित; 11 जिलों में येलो अलर्ट

तिरुवनंतपुरम। केरल में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के उत्तरी हिस्से में मंगलवार को कई जगहों पर तेज बारिश के कारण मिट्टी खिसकने और सड़क पर मलबा आने की घटनाएं सामने आईं। कन्नूर जिले के कई इलाकों में बारिश का असर साफ दिखाई दिया, जहां भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ। मौसम की स्थिति को देखते हुए राज्य के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

कन्नूर जिले के एलायावूर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्थल पर सुरक्षा दीवार गिरने के बाद अचानक मिट्टी खिसक गई और मलबा आसपास के हिस्से में फैल गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक, इसी स्थान पर करीब तीन साल पहले भी बड़ी भूस्खलन की घटना हुई थी। पुराने घटनाक्रम को देखते हुए इस बार भी प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से तत्काल रिपोर्ट मांगी है।

भारी बारिश के कारण जिले के कई हिस्सों में जमीन के धंसने और पहाड़ी क्षेत्रों से मलबा सड़क पर आने का खतरा बढ़ गया है। निर्माण कार्य वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत महसूस की जा रही है, क्योंकि लगातार बारिश से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। प्रशासन की ओर से ऐसे स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है, जहां पहले भी भूस्खलन की घटनाएं हो चुकी हैं।

कन्नूर के पलचुरम इलाके में भी मंगलवार सुबह बारिश के कारण बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टानें सड़क पर आ गईं। बताया गया कि सुबह करीब नौ बजे पलचुरम के चेकुत्थान थोड़ु के पास अचानक मलबा सड़क पर जमा हो गया। इसके चलते इस मार्ग पर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सड़क पर मलबा आने की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत दल सक्रिय हो गए।

जिला कलेक्टर पी. विष्णुराज ने संबंधित अधिकारियों को सड़क से मिट्टी और चट्टानों को जल्द से जल्द हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव दल और राजस्व विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीमों ने स्थिति का जायजा लिया और सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की प्राथमिकता यातायात बहाल करने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रही। लगातार बारिश के कारण प्रशासन ने आने वाले समय में भी भूस्खलन की आशंका जताई है। पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में लगातार पानी जमा होने से मिट्टी कमजोर पड़ सकती है, जिससे अचानक मलबा नीचे आने का खतरा बना रहता है। ऐसे में लोगों को बिना जरूरत संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी गई है।

जिला प्रशासन ने विशेष रूप से पर्यटकों और ऐसे वाहन चालकों से प्रभावित क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की है, जिनका वहां जाना जरूरी नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि मौसम सामान्य होने तक जोखिम वाले रास्तों पर अनावश्यक आवाजाही परेशानी बढ़ा सकती है। लोगों से स्थानीय प्रशासन और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने को कहा गया है।

एलायावूर में प्रभावित स्थल का निरीक्षण भी किया गया। राज्य के बिजली मंत्री सनी जोसेफ, विधायक टीओ मोहानन और जिला कलेक्टर पी. विष्णुराज ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्र, सड़क की स्थिति और आगे की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। प्रशासन ने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बारिश के कारण केवल सड़क यातायात ही प्रभावित नहीं हो रहा, बल्कि निर्माणाधीन परियोजनाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां मिट्टी और चट्टानों के खिसकने का खतरा अधिक हो सकता है। इसलिए प्रशासन और निर्माण एजेंसियों के सामने लोगों को सुरक्षित रखने के साथ-साथ निर्माण स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती है। मौसम की प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए राज्य के कई जिलों में निगरानी बढ़ा दी गई है।

समुद्र की गहराइयों का नया प्रहरी बनेगा ‘निपुण’, नौसेना की बढ़ेगी अंडरवाटर ताकत

मुंबई। भारतीय नौसेना की समुद्र के भीतर निगरानी, गोताखोरी और बचाव क्षमता को और मजबूती मिलने जा रही है। नौसेना का दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोत ‘निपुण’ 31 अगस्त को नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित होने वाले समारोह में इसे औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। विशेष रूप से गहरे समुद्र में गोताखोरी, पानी के नीचे जटिल अभियानों और पनडुब्बी बचाव से जुड़े कार्यों के लिए तैयार किया गया यह पोत नौसेना की अंडरवाटर ऑपरेशनल क्षमता में महत्वपूर्ण इजाफा करेगा।

‘निपुण’ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समुद्र की सतह पर सामान्य जहाजों की तरह केवल परिवहन या निगरानी तक सीमित न रहे, बल्कि पानी के नीचे चलने वाले कठिन और तकनीकी अभियानों में भी लंबे समय तक सहायता उपलब्ध करा सके। समुद्र की गहराई में किसी वस्तु की तलाश, पानी के भीतर किसी संरचना की जांच, तकनीकी हस्तक्षेप या किसी आपात स्थिति में बचाव अभियान जैसे कार्यों में इस पोत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

भारतीय नौसेना के लिए समुद्र के भीतर होने वाले अभियानों की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं। गहरे पानी में दृश्यता कम होना, अत्यधिक दबाव, तेज धाराएं और लंबे समय तक पानी के भीतर काम करने की आवश्यकता गोताखोरों के सामने कठिन परिस्थितियां पैदा करती है। ऐसे अभियानों में केवल प्रशिक्षित गोताखोर पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उनके पीछे आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा सपोर्ट पोत भी जरूरी होता है, जो उन्हें आवश्यक उपकरण, तकनीकी सहायता, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित संचालन का आधार उपलब्ध करा सके। ‘निपुण’ इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

यह पोत निस्तार श्रेणी का दूसरा डाइविंग सपोर्ट पोत है। इस श्रेणी के पोतों को भारतीय नौसेना की अंडरवाटर सपोर्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। स्वदेशी निर्माण के कारण यह भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

‘निपुण’ में आधुनिक गोताखोरी प्रणालियां लगाई गई हैं। इनके माध्यम से नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोर कठिन समुद्री परिस्थितियों में लंबे समय तक अपने अभियानों को अंजाम दे सकेंगे। गहरे समुद्र में काम करने वाले गोताखोरों के लिए पानी के भीतर सुरक्षित तरीके से उतरना, मिशन पूरा करना और फिर सतह पर लौटना बेहद तकनीकी प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया में सपोर्ट पोत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।

पोत में पानी के नीचे होने वाले हस्तक्षेप अभियानों के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि समुद्र के भीतर किसी वस्तु, उपकरण या संरचना की जांच करनी हो अथवा किसी तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए गोताखोरों को पानी के नीचे भेजना हो, तो ‘निपुण’ इस तरह के अभियानों के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सकेगा। इससे नौसेना की समुद्री इंजीनियरिंग और अंडरवाटर ऑपरेशन क्षमता को मजबूती मिलेगी।

‘निपुण’ की एक महत्वपूर्ण भूमिका पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी होगी। समुद्र की गहराई में किसी पनडुब्बी के संकट में फंस जाने की स्थिति बेहद गंभीर होती है। ऐसी परिस्थिति में समय सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। बचाव अभियान के दौरान विशेषज्ञ गोताखोरों, तकनीकी उपकरणों, चिकित्सा सहायता और पानी के नीचे काम करने वाली प्रणालियों की जरूरत होती है। डाइविंग सपोर्ट पोत इस पूरी प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम कर सकता है।

पनडुब्बियों के संचालन में सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहती है। यदि किसी तकनीकी कारण, दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति के कारण पनडुब्बी समुद्र के भीतर फंस जाती है, तो बचाव अभियान को बेहद सावधानी और तकनीकी दक्षता के साथ चलाना पड़ता है। ऐसे में ‘निपुण’ जैसे पोत नौसेना को संकट की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता देते हैं। पोत में चिकित्सकीय सहायता से जुड़ी सुविधाएं भी मौजूद हैं।

बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मतदाता सूची से जुड़े लंबित मामलों का मांगा पूरा हिसाब

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से लंबित अपीलों और उनके निपटारे से जुड़ा विस्तृत आंकड़ा मांगा। शीर्ष अदालत ने आयोग से यह बताने को कहा कि SIR के बाद मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने को चुनौती देने वाली कितनी अपीलें ट्रिब्यूनल के सामने लंबित हैं और अब तक कितने मामलों का निपटारा किया जा चुका है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए, ताकि मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मामलों में अनिश्चितता लंबे समय तक बनी न रहे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान पीठ ने चुनाव आयोग से एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा। अदालत यह जानना चाहती है कि ट्रिब्यूनलों के सामने कुल कितनी अपीलें लंबित हैं और इन मामलों की प्रकृति क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि लंबित अपीलों का अलग-अलग विवरण उपलब्ध कराया जाए। इनमें उन मतदाताओं से जुड़े मामलों की संख्या बताने को कहा गया है, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं या जिनके नाम सूची में शामिल किए गए हैं और उन्हें लेकर आपत्ति अथवा अपील दायर की गई है। इसके साथ ही ऐसी क्रॉस-अपीलों की संख्या भी बतानी होगी, जो संबंधित पक्षों की ओर से दायर की गई हैं।

अदालत का यह निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होना या हटना सीधे उसके मतदान के अधिकार से जुड़ा विषय है। यदि किसी नागरिक को सूची से बाहर कर दिया जाता है और वह इसके खिलाफ अपील करता है, तो उस अपील का समय पर निपटारा होना जरूरी है। इसी तरह किसी व्यक्ति का नाम सूची में शामिल किए जाने

को लेकर आपत्ति हो तो उसके निपटारे की भी स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत के सामने एक महत्वपूर्ण चिंता रखी। उन्होंने कहा कि लोगों को यह स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है कि ट्रिब्यूनलों के सामने कितनी अपीलें लंबित हैं और उनमें से कितने मामलों का फैसला हो चुका है। उनका कहना था कि इस संबंध में सार्वजनिक तौर पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिससे नागरिकों के लिए यह जानना मुश्किल हो रहा है कि उनके मामले की स्थिति क्या है।

याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से विस्तृत आंकड़े मांगने का निर्देश दिया। अदालत यह भी जानना चाहती है कि मौजूदा मामलों का समय पर निपटारा करने के लिए कितने ट्रिब्यूनलों की आवश्यकता है। यदि लंबित मामलों की संख्या अधिक है और मौजूदा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव है, तो क्या नए ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत पड़ेगी, इस पर भी चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची में नामों का सत्यापन और आवश्यक सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना होता है, लेकिन इसके दौरान नाम हटाए जाने या नए नाम शामिल किए जाने को लेकर विवाद भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित नागरिकों को आपत्ति और अपील का अवसर मिलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का प्रभाव व्यापक हो सकता है। राज्य में बड़ी संख्या में मतदाता हैं और चुनावी प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची की शुद्धता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक ओर जहां फर्जी या अपात्र नामों को हटाने की जरूरत होती है, वहीं दूसरी ओर वास्तविक और पात्र मतदाताओं का नाम गलती से सूची से बाहर न हो, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसी संतुलन को लेकर दिखाई देती है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि मतदाता सूची से संबंधित विवादों का निपटारा केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक मामलों पर समयबद्ध तरीके से फैसला हो। इसके लिए लंबित मामलों की संख्या, उनके प्रकार और निपटारे की स्थिति का स्पष्ट डेटा सामने आना जरूरी है।

अदालत ने चुनाव आयोग से यह भी बताने को कहा है कि मौजूदा ट्रिब्यूनल व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं। यदि बड़ी संख्या में अपीलें लंबित हैं तो मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल की जरूरत हो सकती है। इससे सुनवाई की प्रक्रिया में तेजी आने और नागरिकों को अपने मतदाता अधिकार से जुड़े मामलों में समय पर राहत मिलने की संभावना बढ़ सकती है। मामले में एक अहम मुद्दा पारदर्शिता का भी है। यदि मतदाता को यह जानकारी ही नहीं मिले कि उसकी अपील किस स्थिति में है, कितने मामले लंबित हैं और उनका निपटारा कब तक होगा, तो पूरी प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आंकड़ों के साथ स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

अदालत के निर्देश के बाद अब चुनाव आयोग को ट्रिब्यूनलों में लंबित मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर अदालत के समक्ष रखना होगा। इसमें यह बताना होगा कि कितने मामले मतदाता सूची से नाम हटाने से जुड़े हैं, कितने नाम शामिल करने से संबंधित हैं और कितने मामलों में क्रॉस-अपील दायर की गई है। साथ ही आयोग को यह भी बताना होगा कि अब तक कितने मामलों का निपटारा हो चुका है।

यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक और कानूनी स्तर पर बहस जारी है। मतदाता सूची में नाम होना किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में नागरिक की भागीदारी का आधार है। इसलिए सूची के पुनरीक्षण के दौरान प्रशासनिक सटीकता के साथ-साथ नागरिकों के लिए शिकायत और अपील की प्रभावी व्यवस्था भी आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार के निर्देश से यह स्पष्ट है कि अदालत केवल SIR की प्रक्रिया पर ही नहीं, बल्कि उसके बाद पैदा होने वाले विवादों के निपटारे की व्यवस्था पर भी नजर रख रही है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं या जिनके नाम शामिल किए गए हैं, उनसे जुड़े विवादों का निपटारा उचित प्रक्रिया के तहत और समय सीमा में हो। अब चुनाव आयोग के जवाब पर सबकी नजर रहेगी। आयोग को लंबित अपीलों की संख्या और उनकी श्रेणीवार स्थिति बताने के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि मामलों के निपटारे में कितना समय लग रहा है और लंबित मामलों को तेजी से खत्म करने के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से साफ है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण केवल नाम जोड़ने या हटाने की प्रशासनिक कवायद नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हर विवाद का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान भी उतना ही जरूरी है। अब चुनाव आयोग के आंकड़ों से यह तस्वीर साफ होगी कि पश्चिम बंगाल में SIR के बाद कितने मतदाता अपील की प्रक्रिया में हैं और उनके मामलों के निपटारे की रफ्तार क्या है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

राजनीति न करें, सुधार हो मकसद

देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। जिस देश में एक लाख स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हों, मूलभूत शैक्षिक सुविधाओं का अभाव हो, वहां पढ़ाई का स्तर क्या होगा, अंदाज लगाना कठिन नहीं है। कुछ स्कूल जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ पेड़ तले व बरामदों में- तो सवाल स्वाभाविक है कि सुधार क्यों नहीं होता? आखिर इन स्कूलों का सुधार हमारे नीति-नियंताओं की प्राथमिकताओं में क्यों नहीं होता? जिस शिक्षा विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की पूरी फौज तैनात है, उसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होती? अब भले ही सरकारी स्कूलों को सीजेपी ने अपना मुद्दा बना लिया हो, लेकिन इससे पहले ही देश के कई भागों में छात्र स्कूलों में सुधार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। विडंबना यह है कि इन स्कूलों पर ग्रामीण, समाज के वंचित वर्गों, श्रमिकों व गरीब बच्चों की निर्भरता अधिक होती है, फलतः उनकी आवाज भी अनसुनी कर दी जाती है। यदि नेताओं और अधिकारियों के बच्चों के लिये सरकारी स्कूलों में भर्ती अनिवार्य कर दी जाती तो शायद इन स्कूलों के दिन फिर जाते। सरकारी स्कूलों का सच किसी से छिपा नहीं है। नीति आयोग के हालिया आंकड़े इस सच को अनावृत करते हैं। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दशक में पूरे देश में 94 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। साथ ही इसी अवधि में सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल भी 83 हजार से घटकर 79 हजार रह गये हैं। स्कूलों में छात्रों के दाखिले में कमी का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मुनाफा कमा रहे निजी स्कूलों का कुनबा लगातार बढ़ ही रहा है। उनकी संख्या अब 2.9 लाख से बढ़कर 3.4 लाख के करीब हो गई है। यह एक हकीकत है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर राजनीतिक दलों की जो फिक्र सामने आ रही है, उसके निहितार्थ समझना कठिन नहीं है। इन दलों की सरकारों के दौरान भी इन स्कूलों की दिशा-दशा में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया।

चिंता इस बात को लेकर है कि इस मुद्दे पर जो राजनीति हो रही है, कहीं उसके चलते सुधार के विमर्श पर आंच न आए। सही मायने में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होना चाहिए। इसमें शासन, प्रशासन, पक्ष-विपक्ष और नागरिकों की भी अहम भूमिका होनी चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि अभिभावकों से मोटी फीस लेने वाले निजी स्कूल क्यों फल-फूल रहे हैं? सरकारी स्कूलों के पास भवन हैं, पर्याप्त जगह है, सम्मानजनक पगार वाले शिक्षक हैं और सरकारी तंत्र का समर्थन है, तो ये स्कूल पनप क्यों नहीं रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में पानी, बिजली, बेंच, टेबल व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं? बल्कि सुधारों के बजाय शिक्षकों की नियुक्ति में राजनेताओं की धांधली की खबरें अकसर मीडिया में तैरती रहती हैं। विडंबना देखिये कि पढ़ाई-लिखाई के लिये अनुकूल वातावरण की मांग को लेकर राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। इन बच्चों को अपने भविष्य की फिक्र थी और ये स्कूलों में गुणवत्ता का शैक्षिक वातावरण मांग रहे थे। निश्चित रूप से हमारे नीति-नियंताओं ने सरकारी स्कूलों का उद्धार करने के लिये कभी कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। अब जब मुद्दा तूल पकड़ रहा है तो तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। सही मायने में प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश के भविष्य की बुनियाद होती है। जब इन स्कूलों में बीमार भविष्य वाले नागरिक तैयार करेंगे तो देश का भला कैसे होगा? दरअसल, सरकारी स्कूल हमारे समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता का पर्याय हैं। जो लोग अपने बच्चों को महंगे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वे ही अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिये मजबूर हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह कि मिड-डे-मील जैसे प्रलोभनों से ये सरकारी स्कूल कब तक अपना अस्तित्व बना पाएंगे? कहीं न कहीं इन स्कूलों की अनदेखी करके हम एक बड़ी आबादी को शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित तो नहीं कर रहे हैं?

लापरवाही और भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी

> "सवाल है कि क्या हर बार की बाढ़ व जलभराव समस्या हमारी व्यवस्था की लापरवाही या भ्रष्टाचार है? जहां हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर पैसा खर्च होता है, लेकिन अगली बारिश में वही नाले फिर जाम मिलते हैं। जल निकासी की परियोजनाएं बार-बार बनती हैं, लेकिन जलभराव खत्म नहीं होता, वहां काम की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?

आज सबसे बड़ा सवाल है कि जलभराव के बाद राहत क्यों, संकट आने से पहले तैयारी क्यों नहीं? अधिकांश शहरी जलभराव अचानक पैदा होने वाली समस्या नहीं है। जिन स्थानों पर हर वर्ष पानी भरता है, उनकी पहचान प्रशासन और नगर निकायों को पहले से होती है। यह भी पता होता है कि किस सड़क पर पानी जमा होता है, किस नाले की क्षमता कम है और कहां प्राकृतिक जल निकासी बाधित है। फिर भी हमारा जोर अक्सर पानी भरने के बाद राहत देने पर रहता है, पानी भरने से पहले समस्या रोकने पर नहीं।

इस वर्ष असम में बाढ़ से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों का दुख है। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के कारण हर वर्ष बाढ़ का खतरा रहता है। केवल भारी बारिश को जिम्मेदार बताकर हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बाढ़ क्षेत्र पर बढ़ता दबाव, प्राकृतिक जल क्षेत्रों का नुकसान, अनियोजित निर्माण और कमजोर पूर्व चेतावनी व्यवस्था आपदा को अधिक विनाशकारी बना सकती है।

हरियाणा की आर्थिक शक्ति गुरुग्राम और देश के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में शामिल इस शहर में लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन मानसून आते ही कई बार इसकी तस्वीर बदल जाती है। भारी बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबती हैं, वाहन घंटों फंसते हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होता है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाती है। हर वर्ष नालों की सफाई, पंपों की व्यवस्था और जल निकासी के इंतजाम किए जाते हैं। फिर अगले मानसून में वही स्थान दोबारा पानी में दिखाई देते हैं। पानी भरने के बाद पंप लगाना जरूरी है, लेकिन पंप स्थायी समाधान नहीं है। जलभराव के बाद यातायात नियंत्रित करना जरूरी है, लेकिन उससे बेहतर है कि यातायात प्रभावित ही न हो। पानी निकालना जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी है कि पानी जमा ही न हो। गुरुग्राम की समस्या को केवल अत्यधिक बारिश कहकर समझना अधूरा होगा। तेजी से बढ़ते निर्माण ने जमीन की पानी सोखने की क्षमता कम कर दी है। जहां कभी खाली जमीन, तालाब, हरित क्षेत्र और प्राकृतिक जल मार्ग थे, वहां सड़कें और इमारतें खड़ी हो गई हैं। बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहता है और पर्याप्त निकासी न मिलने पर सड़कें जलाशय बन जाती हैं। इस समस्या से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और देश के अनेक शहर हर वर्ष सामना करते हैं। हमने शहरों का विस्तार तो कर दिया, लेकिन पानी के लिए जगह नहीं छोड़ी। तालाब, झील और प्राकृतिक जल क्षेत्र खाली जमीन नहीं, बल्कि शहरों की प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था हैं।

सवाल है कि क्या हर बार की बाढ़ व जलभराव समस्या हमारी व्यवस्था की लापरवाही या भ्रष्टाचार है? जहां हर वर्ष नालों की सफाई के नाम पर पैसा खर्च होता है, लेकिन अगली बारिश में वही नाले फिर जाम मिलते हैं। जल निकासी की परियोजनाएं बार-बार बनती हैं, लेकिन जलभराव खत्म नहीं होता, वहां काम की गुणवत्ता और खर्च की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर किसी अधिकारी, ठेकेदार या एजेंसी की लापरवाही से सार्वजनिक धन खर्च होने के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो जवाबदेही किसकी होगी? भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, स्वतंत्र गुणवत्ता जांच और प्राकृतिक जल मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रत्येक बड़े शहर का वैज्ञानिक बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट रहे कि अत्यधिक बारिश में पानी किस दिशा में जाएगा।

मानसून से पहले नालों की सफाई भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। सफाई से पहले और बाद की स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाए। हर बड़े जलभराव के बाद केवल पानी निकालने की रिपोर्ट न बने, बल्कि यह भी बताया जाए कि पानी क्यों भरा और अगली बार इसे रोकने के लिए क्या किया जाएगा। शहरों में समय पर बाढ़ चेतावनी की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। भारी बारिश की सूचना पहले मिले, यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाए और संवेदनशील इलाकों में प्रशासन पहले से तैनात हो।

गुरुग्राम का जलभराव बताता है कि आधुनिक शहर केवल ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं बनता। आधुनिक शहर वह है जो भारी बारिश के दौरान भी अपने नागरिकों को सुरक्षित रख सके। बारिश हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जल निकासी की योजना, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, निर्माण पर नियंत्रण, नालों का रखरखाव, पूर्व चेतावनी, विभागों का समन्वय और सार्वजनिक धन में पारदर्शिता हमारे हाथ में है।

अब समय आ गया है कि मानसून के बाद राहत की खबरों के बजाय मानसून से पहले तैयारी की खबरें सुर्खियां बनें। किसी शहर में प्रशासन की असली सफलता यह नहीं कि उसने बाढ़ के बाद कितनी तेजी से पानी निकाला।

प्रेरणा

हार मानने से पहले एक कदम और

अरावली की पहाड़ियों पर सूरज ढल चुका था। आसमान पर लालिमा धीरे-धीरे गहरी होती जा रही थी और पहाड़ों के बीच फैली घाटियों में अंधेरा उतरने लगा था। दूर कहीं पक्षियों के लौटने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उन शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटी-सी सेना आने वाले संघर्ष की तैयारी कर रही थी। सामने एक ऐसी विशाल सेना थी, जिसकी संख्या देखकर किसी भी योद्धा के मन में भय पैदा हो सकता था। बप्पा रावल अपने सैनिकों के बीच खड़े थे और उनकी नजरें सामने फैली पहाड़ियों पर टिकी थीं।

एक सैनिक ने धीरे से कहा, "बप्पा, हमारे पास बहुत कम सैनिक हैं। सामने की सेना हमसे कई गुना बड़ी है। क्या ऐसी स्थिति में पीछे हटना ही उचित नहीं होगा?"

कुछ क्षणों तक बप्पा रावल ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने चारों ओर देखा। ऊंचे पहाड़, संकरी घाटियां, चट्टानों के बीच से निकलती पगडंडियां और अंधेरे में खोते रास्ते। फिर उन्होंने सैनिक की ओर देखा और कहा, "पीछे हटना आसान है, लेकिन क्या हर आसान रास्ता सही रास्ता होता है?"

सैनिक चुप रहा।

बप्पा रावल ने कहा, "हम दुश्मन की ताकत से मुकाबला उसकी तरह नहीं करेंगे। उसके पास संख्या अधिक है, लेकिन हमारे पास इस भूमि की पहचान है। वह मैदान में अपनी शक्ति दिखा सकता है, लेकिन इन पहाड़ियों में हमारी समझ उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।"

उनकी बात सुनकर सैनिकों में नई ऊर्जा पैदा हुई। बप्पा रावल ने अपनी सेना को कई छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। कुछ सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर चले गए, कुछ घाटियों के बीच छिप गए और कुछ को ऐसी जगह तैनात किया गया, जहां से वे अचानक हमला करके वापस सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। रात गहराती गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी एक पहाड़ी पर मशाल जली। कुछ देर बाद दूसरी दिशा में एक और मशाल दिखाई दी। फिर तीसरी और चौथी दिशा से भी रोशनी दिखाई देने लगी। घोड़ों की टापें कभी एक ओर से सुनाई देतीं तो कभी दूसरी ओर से। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ियों के भीतर कोई विशाल सेना लगातार अपनी स्थिति बदल रही हो।

दुश्मन की सेना इस दृश्य को देखकर भ्रमित हो गई। उसे समझ नहीं आया कि सामने वास्तव में कितने सैनिक हैं। रात के अंधेरे और पहाड़ियों की बनावट ने छोटी सेना को बड़ी सेना का रूप दे दिया था।

सुबह होने से पहले ही दुश्मन ने आगे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही सैनिक संकरी घाटी में पहुंचे, अचानक एक छोटी टुकड़ी ने हमला कर दिया। दुश्मन संभलता, उससे पहले दूसरी दिशा से सैनिकों ने हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में वे सैनिक पहाड़ियों के पीछे गायब हो गए।

दुश्मन को लगा कि चारों ओर से उस पर हमला हो रहा है। उसने अपनी सेना को अलग-अलग दिशाओं में भेजा, लेकिन इससे उसकी व्यवस्था और बिगड़ गई। बड़ी संख्या अब उसके लिए ताकत नहीं बल्कि परेशानी बन गई थी।

एक सैनिक ने बप्पा रावल के पास आकर कहा, "बप्पा, यह कैसे संभव हुआ? हमारी सेना इतनी छोटी थी और फिर भी हमने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया।" बप्पा रावल ने कहा, "क्योंकि जीत हमेशा ताकत की मात्रा से नहीं होती। जीत इस बात से होती है कि उपलब्ध ताकत का उपयोग किस तरह किया जाता है। जिसने परिस्थिति को समझ लिया, उसने आधी लड़ाई वहीं जीत ली।"

यह बात केवल युद्ध की कहानी नहीं है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब हम अपने सामने खड़ी समस्या को देखकर डर जाते हैं। हमें लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है और हमारे पास उसका सामना करने की क्षमता बहुत छोटी। हम दूसरों के साधन देखते हैं और अपनी कमी गिनने लगते हैं। धीरे-धीरे हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है और हम उस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं।

लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कठिनाई का आकार देखकर अपनी क्षमता का फैसला नहीं करना चाहिए। पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, चढ़ाई एक-एक कदम से ही पूरी होती है। समुद्र कितना भी विशाल हो, यात्रा एक-एक लहर को पार करके ही पूरी होती है। उसी तरह बड़ी समस्या भी छोटे-छोटे प्रयासों से हल होती है।

कई बार हमें पूरी मंजिल दिखाई नहीं देती। केवल इतना पता होता है कि हमें अभी एक कदम आगे बढ़ना है। यही एक कदम भविष्य बदल सकता है। जो व्यक्ति अंधेरे में भी पहला कदम उठाने का साहस करता है, वही धीरे-धीरे अपने लिए रास्ता बनाता है।

असफलता आने पर भी यही बात याद रखनी चाहिए। असफलता यह नहीं कहती कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। वह केवल यह बताती है कि जिस तरीके से आपने प्रयास किया, उसमें बदलाव की जरूरत है। रास्ता बदलना हार नहीं है। कभी-कभी रास्ता बदलना ही सफलता की शुरुआत होता है। जीवन में ऐसे भी दिन आते हैं, जब मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। तब मन कहता है कि अब और प्रयास करने से क्या फायदा। लेकिन अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर केवल एक और प्रयास का होता है। जिस व्यक्ति ने आखिरी क्षण तक प्रयास जारी रखा, वही उस दरवाजे को खोल पाया, जिसे बाकी लोग बंद समझकर लौट गए। इसलिए जब कभी लगे कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, तब अपनी कमियों को गिनने के बजाय अपनी संभावनाओं को पहचानिए। जब रास्ता कठिन हो, तो कदम छोटे कर लीजिए, लेकिन कदम रोकिए मत। जब मंजिल दूर लगे, तो केवल अगले पड़ाव के बारे में सोचिए। जब उम्मीद कमजोर हो, तो अपने पुराने संघर्षों को याद कीजिए और देखिए कि आपने कितनी कठिन परिस्थितियां पहले ही पार की हैं।

क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं। सबसे बड़ी हार तब होती है जब गिरने के बाद उठने से इनकार कर देते हैं। रास्ते बंद हो सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, साधन कम हो सकते हैं, लेकिन जब तक भीतर साहस जीवित है, तब तक संभावना भी जीवित है।

याद रखिए, मुश्किल रास्ते अक्सर मजबूत लोगों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब हार मानने से पहले बस एक कदम और बढ़ाइए। हो सकता है, वही एक कदम आपकी जिंदगी की नई राह बन जाए।

गड़बड़ा जाएंगे सभी राजनीतिक दलों के समीकरण ? 2029 से ही One Nation One Election को लागू करने की तैयारी तेज !

भले ही देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए अपनी-अपनी बिसात बिछाने में जुटी हों, लेकिन भारतीय राजनीति की इस शतरंज पर जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा 'मास्टरस्ट्रोक' चलने की संभावना जोर पकड़ रही है। हम आपको बता दें कि 'एक देश, एक चुनाव' का विचार अब महज बहस या चुनावी नारा नहीं रह गया है, भारत इसके क्रियान्वयन से कुछ ही कदम दूर दिखाई दे रहा है। एक ओर भाजपा देशभर में विभिन्न सामाजिक और पेशेवर वर्गों के बीच इस विचार के समर्थन में अभियान चलाकर जनमत तैयार करने में जुटी है, वहीं इस मुद्दे पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति भी राज्यों, विधायिकाओं, शिक्षाविदों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के चरण में पहुंच रही है। ऐसे में सियासी हलकों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या चुनावी राजनीति की मौजूदा बिसात बदलने वाली है और क्या 'एक देश, एक चुनाव' मोदी सरकार की अगली बड़ी राजनीतिक चाल साबित होगी। हम आपको बता दें कि मौजूदा विधेयकों की मूल रूपरेखा के अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक चक्र में लाने की पहली वास्तविक संभावना 2034 से बनती है। संसद की संयुक्त समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही है। इन प्रावधानों का उद्देश्य अगले चुनाव चक्र में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ लाना है। लेकिन राजनीतिक सत्ता का गणित शायद अब 2034 तक इंतजार करने के मूड में नहीं है।

एनडीए के शासन वाले 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 11 में अगले दो वर्षों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं। यदि इन राज्यों में एनडीए अपनी सरकारें बरकरार रखता है, तो 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ इन्हें चुनावी चक्र में लाने के लिए जनवरी 2029 तक विधानसभाएं भंग करने का विकल्प सामने आ सकता है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा में विधानसभा चुनाव पहले से ही लोकसभा चुनाव के साथ होते रहे हैं। इस प्रकार इन चार राज्यों को समन्वित चुनावी चक्र में लाना अपेक्षाकृत आसान होगा।

इसके अलावा, संवैधानिक रास्ता भी राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है, हालांकि सामान्य परिस्थितियों में यह फैसला मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। विधानसभा भंग होने के बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराना आवश्यक होता है। यही वह संवैधानिक खिड़की है, जिसके जरिए 2029 के साथ चुनावों का समन्वय करने की राजनीतिक संभावना तलाशी जा रही है।

यहीं से 'एक देश, एक चुनाव' का प्रशासनिक तर्क सीधे राजनीतिक रणनीति में बदल जाता है। सवाल यह है कि क्या किसी निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल तीन या चार वर्ष तक घटाकर चुनावी चक्र को एक साथ लाना महज चुनाव सुधार होगा, या फिर यह सत्ता की सुविधानुसार राजनीतिक कैलेंडर को पुनर्गठित करने की शुरुआत होगी? एनडीए के लिए यह योजना चुनावी संसाधनों, संगठनात्मक ताकत और राष्ट्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता को एक साथ मैदान में उतारने का अवसर बन सकती है। एक ही समय में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने पर राष्ट्रीय मुद्दों की लहर राज्य-स्तरीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

राजनीतिक दृष्टि से यह विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। पंजाब में 2027 और हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम तथा तेलंगाना में 2028 में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनके बाद चुनी जाने वाली विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 के लोकसभा चुनाव तक केवल एक या दो वर्ष पुराना होगा, जबकि यदि भविष्य में उन्हें लोकसभा चुनाव के चक्र से जोड़ा जाता है तो उनकी अवधि को लेकर अलग संवैधानिक और राजनीतिक बहस खड़ी होगी। दूसरी ओर, 2028 में मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा जैसे राज्यों के चुनाव तथा 2029 के आसपास विभिन्न राज्यों के अलग-अलग चुनावी कार्यक्रम देश के मौजूदा बिखरे हुए चुनाव चक्र की जटिलता को दिखाते हैं।

संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी ने इस संभावना पर साफ कहा है कि 2029 में चुनावों को आगे बढ़ाकर एक साथ कराने का फैसला समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और यह संबंधित एनडीए मुख्यमंत्रियों पर निर्भर करेगा। हम आपको याद दिला दें कि यह समिति दिसंबर 2024 में गठित हुई थी और राज्यों में सरकारों, विधायिकाओं, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से संवाद कर रही है। उसकी रिपोर्ट इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र में आने की उम्मीद है। लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर विपक्ष पहले ही अपनी तलवारें खींच चुका है। कांग्रेस का तर्क है कि 'एक देश, एक चुनाव' असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और जवाबदेही की भावना के विरुद्ध है। विपक्ष का सवाल यह भी है कि यदि विधानसभा का जनादेश पांच वर्ष के लिए है, तो उसे राजनीतिक सुविधा के लिए बीच में समाप्त करना मतदाता के अधिकारों और संघीय ढांचे के साथ किस हद तक न्याय करेगा। यह विवाद उस समय और तीखा हो सकता है, जब परिसीमन को लेकर केंद्र और विपक्षी दलों के बीच पहले से ही अविश्वास मौजूद है। दरअसल, 2029 का संभावित प्रयोग केवल चुनावी तारीखें मिलाने की कवायद नहीं होगा। यह भारतीय राजनीति में केंद्र बनाम राज्यों, राष्ट्रीय नेतृत्व बनाम क्षेत्रीय मुद्दों और चुनावी दक्षता बनाम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की नई लड़ाई छेड़ सकता है। एनडीए इसे स्थिरता, कम खर्च और बार-बार लगने वाली आचार संहिता से मुक्ति के रूप में पेश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता और अलग जनादेशों को राष्ट्रीय चुनाव की छाया में समेटने की कोशिश बता कर इसका विरोध कर रहा है। बहरहाल, 2029 का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोकसभा और 22 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे या नहीं। असली सियासी पहेली यह है कि क्या 'एक देश, एक चुनाव' के बहाने भारतीय राजनीति का चुनावी कैलेंडर बदलेगा, या फिर सत्ता के खेल का पूरा बोर्ड ही नए सिरे से सजाया जाएगा?

अभियान

खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव: जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ दिखाई देते हैं

मध्य प्रदेश की धरती अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों और धार्मिक परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब भी खजुराहो का नाम आता है, लोगों के मन में सबसे पहले यहां स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर समूह की तस्वीर उभरती है। लेकिन खजुराहो की पहचान केवल अपनी अद्भुत स्थापत्य कला तक सीमित नहीं है। इसी ऐतिहासिक नगरी में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहां आज भी भगवान शिव की पूजा उसी श्रद्धा और आस्था के साथ की जाती है, जैसी सदियों पहले होती रही होगी। यह मंदिर है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसे खजुराहो के सबसे महत्वपूर्ण जीवित धार्मिक स्थलों में गिना जाता है।

मतंगेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं के लिए केवल एक प्राचीन मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का ऐसा केंद्र है, जहां भगवान शिव के दर्शन करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं। मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। स्थानीय मान्यता है कि यह शिवलिंग समय के साथ धीरे-धीरे बढ़ता है और हर वर्ष इसकी ऊंचाई में लगभग एक इंच की वृद्धि होती है। इस मान्यता ने मंदिर के प्रति लोगों की जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों को और गहरा कर दिया है। हालांकि इस वृद्धि को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण सर्वमान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास आज भी मजबूत है।

मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अत्यंत विशाल है और इसे देखने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्सुकता रहती है। शिवलिंग पर पीतल और अन्य धातुओं का आवरण भी दिखाई देता है। मंदिर का गर्भगृह अपेक्षाकृत गंभीर और आध्यात्मिक वातावरण वाला है। जैसे ही भक्त यहां प्रवेश करते हैं, घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और शिवभक्ति का वातावरण उन्हें अपने आप धार्मिक भावनाओं से भर देता है।

मतंगेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास खजुराहो के चंदेल काल से जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। यह वह समय था जब चंदेल शासकों ने खजुराहो को धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया था। चंदेल शासकों के शासनकाल में यहां अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ और खजुराहो की स्थापत्य परंपरा ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इन्हीं मंदिरों के बीच मतंगेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हुआ।

खजुराहो के दूसरे मंदिरों की तरह मतंगेश्वर मंदिर भी नागर शैली की स्थापत्य परंपरा से प्रभावित दिखाई देता है। मंदिर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है और इसके ऊपर उठता हुआ शिखर दूर से ही अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। मंदिर की वास्तुकला में वह गंभीरता और संतुलन दिखाई देता है, जो प्राचीन भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा की विशेषता रही है। मंदिर के शिखर को धार्मिक दृष्टि से कैलाश पर्वत का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत माना गया है। खजुराहो के मंदिरों की एक खास बात यह है कि यहां धर्म, कला और स्थापत्य एक-दूसरे से अलग नहीं दिखाई देते। मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां उस समय के समाज, जीवन, संस्कृति और धार्मिक सोच की झलक प्रस्तुत करती हैं। मतंगेश्वर मंदिर का स्वरूप अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण है, लेकिन इसका धार्मिक महत्व अत्यंत व्यापक है। यही वजह है कि ऐतिहासिक स्मारकों के बीच स्थित होने के बावजूद यह मंदिर आज भी एक सक्रिय पूजा स्थल है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मतंगेश्वर महादेव मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। शिवभक्तों की बड़ी संख्या मंदिर में पहुंचती है। भगवान शिव का विशेष श्रृंगार किया जाता है और जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। शिवरात्रि के दौरान खजुराहो में धार्मिक उत्सव के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर मेले जैसा वातावरण भी देखने को मिलता है।

सावन के महीने में भी मंदिर में विशेष भीड़ रहती है। भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र महीने में श्रद्धालु जल चढ़ाने और पूजा-अर्चना करने के लिए यहां पहुंचते हैं। कई भक्त दूर-दूर से यात्रा करके आते हैं। कोई परिवार के साथ दर्शन करता है तो कोई अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंचता है। सावन के सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिर में भक्तों की संख्या बढ़ जाती है।

मतंगेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी मान्यताओं की बात करें तो यहां आने वाले श्रद्धालु भगवान शिव को मनोकामना पूरी करने वाला देवता मानते हैं। कई भक्त विवाह, परिवार की सुख-शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन की परेशानियों से मुक्ति के लिए पूजा करते हैं। धार्मिक आस्था का यह स्वरूप पीढ़ियों से लोगों को इस मंदिर से जोड़ता रहा है। मंदिर से जुड़ी सबसे चर्चित मान्यता शिवलिंग के बढ़ने की है। स्थानीय लोगों के बीच यह विश्वास है कि शिवलिंग की ऊंचाई हर वर्ष थोड़ी बढ़ती है। कुछ श्रद्धालु इसे भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति का संकेत मानते हैं। धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव की शक्ति और दिव्यता से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी ओर, इस तरह की मान्यताओं को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग हो सकता है। इसलिए इसे आस्था और स्थानीय परंपरा के रूप में समझना अधिक उचित है। मंदिर का महत्व केवल इस मान्यता पर निर्भर नहीं है; इसका वास्तविक महत्व इसकी प्राचीनता, धार्मिक निरंतरता और खजुराहो की ऐतिहासिक विरासत में इसकी भूमिका से भी जुड़ा है।

अगर कोई व्यक्ति खजुराहो घूमने की योजना बना रहा है, तो मतंगेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा उसके लिए विशेष अनुभव हो सकती है। यहां दर्शन के साथ खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह और आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को भी देखा जा सकता है। खजुराहो की स्थापत्य कला भारतीय इतिहास और कला के अध्ययन में विशेष स्थान रखती है। यहां के मंदिरों की नक्काशी, शिखर, मूर्तियां और वास्तुशैली पर्यटकों को लंबे समय तक आकर्षित करती हैं। दर्शन की दृष्टि से सुबह का समय अधिक शांत और आध्यात्मिक अनुभव दे सकता है। सुबह मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आसपास के अन्य ऐतिहासिक स्थलों को देखा जा सकता है। यदि कोई यात्री गर्मी से बचना चाहता है तो अक्टूबर से मार्च के बीच खजुराहो की यात्रा करना सुविधाजनक माना जाता है। इस दौरान मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है और ऐतिहासिक स्थलों को घूमने में भी आसानी होती है। सावन का समय धार्मिक दृष्टि से विशेष है, हालांकि उस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या अधिक हो सकती है। खजुराहो की यात्रा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रहती। यहां आने वाले पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और बुंदेलखंडी खान-पान का अनुभव भी मिल सकता है। स्थानीय बाजारों में पारंपरिक वस्तुएं और हस्तशिल्प देखने को मिलते हैं। छोटे भोजनालयों और स्थानीय दुकानों पर बुंदेलखंडी स्वाद का आनंद लिया जा सकता है। इस तरह धार्मिक यात्रा के साथ स्थानीय संस्कृति को समझने का अवसर भी मिलता है।

मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचना भी बहुत कठिन नहीं है। खजुराहो हवाई मार्ग से देश के कुछ प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। खजुराहो एयरपोर्ट से शहर और मंदिर क्षेत्र तक टैक्सी या स्थानीय परिवहन की सुविधा ली जा सकती है। रेल मार्ग से आने वाले यात्री खजुराहो रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। स्टेशन से ऑटो, टैक्सी या अन्य स्थानीय साधनों की मदद से मंदिर तक जाया जा सकता है। सड़क मार्ग से भी खजुराहो मध्य प्रदेश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए निजी वाहन या बस से यात्रा की जा सकती है।

मतंगेश्वर महादेव मंदिर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहां इतिहास केवल पत्थरों में बंद नहीं है, बल्कि आज भी पूजा और आस्था के रूप में जीवित दिखाई देता है। खजुराहो के कई मंदिर अपनी ऐतिहासिक और स्थापत्य सुंदरता के कारण प्रसिद्ध हैं, लेकिन मतंगेश्वर मंदिर में प्राचीन विरासत के साथ निरंतर चल रही धार्मिक परंपरा का अनुभव भी होता है।

सदियों का समय बीत गया, राजवंश बदल गए, शासन व्यवस्थाएं बदल गईं और समाज का स्वरूप भी काफी बदल गया, लेकिन भगवान शिव के प्रति लोगों की आस्था आज भी उसी तरह बनी हुई है। मंदिर की घंटियां, शिवलिंग पर चढ़ता जल, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की आंखों में दिखाई देने वाला विश्वास इस बात का एहसास कराता है कि भारतीय संस्कृति में मंदिर केवल पूजा करने की जगह नहीं होते, बल्कि वे इतिहास, परंपरा और समाज की स्मृतियों को भी अपने भीतर संजोकर रखते हैं। खजुराहो आने वाला कोई भी यात्री यदि केवल प्रसिद्ध मंदिरों को देखकर लौट जाता है, तो वह इस प्राचीन नगरी के एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पक्ष से परिचित होने से रह सकता है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पीएम मोदी से मिले गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, थराद की महिला कारीगरों की खास शॉल ने खींचा ध्यान

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकरभाई चौधरी ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गुजरात से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ सहकारिता, कृषि, प्रकृति और किसानों-पशुपालकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान शंकर चौधरी ने प्रधानमंत्री को गुजरात के थराद क्षेत्र की महिला कारीगरों द्वारा हाथों से तैयार की गई पारंपरिक शॉल भेंट की। इस शॉल को स्थानीय महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया गया।

शंकर चौधरी ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को आत्मीय बताया और कहा कि गांव, गरीब, युवा और किसान हितों को प्राथमिकता देने वाले प्रधानमंत्री से विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में सहकारिता, प्रकृति और कृषि सहित कई विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। शंकर चौधरी ने प्रधानमंत्री के किसान और पशुपालक हितों से जुड़े प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अन्नदाता के हितों को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। उनके मुताबिक, वैश्विक स्तर पर कई तरह के दबावों के बावजूद सरकार ने दूध के आयात से जुड़े मुद्दों पर देश के पशुपालकों के हितों को महत्व दिया है। उन्होंने इसे पशुपालक समुदाय के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुलाकात के दौरान गोबर-धन योजना का भी उल्लेख किया गया। शंकर चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गोबर-धन से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

हालांकि इस मुलाकात का सबसे खास आकर्षण थराद की महिला कारीगरों द्वारा तैयार की गई शॉल रही। शंकर चौधरी ने यह शॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करते हुए इसे गुजरात की मातृशक्ति के हुनर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि शॉल को तैयार करने वाली महिलाओं की मेहनत और पारंपरिक कला इस उपहार को विशेष बनाती है।

थराद के शिवनगर क्षेत्र की महिला कारीगरों द्वारा तैयार की गई यह शॉल पारंपरिक सूफ कढ़ाई के लिए जानी जाती है। सूफ कढ़ाई गुजरात की पारंपरिक हस्तशिल्प कला की एक विशिष्ट शैली है, जिसमें कारीगर अपनी बारीक कारीगरी और धागों की गिनती के आधार पर कपड़े पर डिजाइन तैयार करते हैं। इस कला की खासियत यह है कि कपड़े पर पहले से डिजाइन या पैटर्न नहीं छापा जाता।

कारीगर कपड़े के धागों को गिनकर अपनी कल्पना और अनुभव के आधार पर ज्यामितीय तथा पारंपरिक आकृतियां तैयार करते हैं। यही वजह है कि इस तरह तैयार होने वाली प्रत्येक कढ़ाई में कारीगर की व्यक्तिगत कुशलता और मेहनत की छाप दिखाई देती है। इसमें छोटी-छोटी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और डिजाइन को संतुलित रूप देने के लिए लंबे अनुभव की जरूरत होती है।

थराद की इस शॉल को तैयार करने वाली महिला कारीगरों के लिए यह केवल हस्तशिल्प का काम नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक कला को जीवित रखने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का माध्यम भी है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पारंपरिक हस्तकला को आगे बढ़ाना स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शंकर चौधरी ने प्रधानमंत्री को शॉल भेंट करने के बाद इसे थराद की महिलाओं की मेहनत और हुनर से जोड़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस आत्मीयता से इसे स्वीकार किया, वह स्थानीय महिला कारीगरों के लिए गौरव की बात है। उनके मुताबिक, इस तरह की पारंपरिक कलाओं को पहचान मिलने से कारीगरों का उत्साह बढ़ता है और नई पीढ़ी भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ती है।

गुजरात में हस्तशिल्प और पारंपरिक कढ़ाई की विभिन्न शैलियां लंबे समय से ग्रामीण जीवन और स्थानीय संस्कृति का हिस्सा रही हैं। इन कलाओं में केवल कपड़े को सजाने की कला नहीं होती, बल्कि इनके पीछे पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, स्थानीय जीवनशैली और कारीगरों का अनुभव भी जुड़ा होता है। थराद की सूफ कढ़ाई भी इसी समृद्ध परंपरा का हिस्सा मानी जाती है।

प्रधानमंत्री को भेंट की गई शॉल ने इस पारंपरिक कला को राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने का अवसर दिया है। एक ओर जहां शंकर चौधरी और प्रधानमंत्री के बीच कृषि, सहकारिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर थराद की महिला कारीगरों का हस्तनिर्मित उत्पाद इस मुलाकात में स्थानीय कला और महिला सशक्तीकरण का संदेश लेकर पहुंचा।

शंकर चौधरी की प्रधानमंत्री से मुलाकात ऐसे समय में हुई, जब गुजरात के कई मंत्री भी दिल्ली के दौरे पर हैं। ऐसे में गुजरात से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और विकासात्मक विषयों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक और सरकारी स्तर पर गतिविधियां जारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष की प्रधानमंत्री से मुलाकात में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और पशुपालकों से जुड़े विषयों पर चर्चा को भी इसी व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। मुलाकात के दौरान कृषि और पशुपालन से जुड़े मुद्दों पर जोर इस बात को भी रेखांकित करता है कि गुजरात की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसान और पशुपालक कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूध उत्पादन, सहकारिता और पशुपालन गुजरात की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़े क्षेत्र हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और योजनाओं पर चर्चा राज्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।

थराद की शॉल इस मुलाकात का सांस्कृतिक पक्ष भी सामने लाती है। जिस क्षेत्र की महिलाएं अपने हाथों से पारंपरिक कढ़ाई तैयार करती हैं, वहां की कला को देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचाना स्थानीय कारीगरों के लिए सम्मान का विषय है। यह इस बात का भी उदाहरण है कि पारंपरिक हस्तशिल्प को सरकारी और सार्वजनिक मंचों के माध्यम से पहचान दिलाकर ग्रामीण महिलाओं के हुनर को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सूफ कढ़ाई की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बारीकी और गणना आधारित डिजाइन प्रक्रिया है। कारीगर कपड़े पर धागों की संरचना को समझते हुए एक-एक पैटर्न तैयार करते हैं। इसमें किसी मशीन या पहले से छपे डिजाइन पर निर्भरता कम होती है। यही कारण है कि इस कला को तैयार करने के लिए धैर्य, अनुभव और बेहद सटीक हाथ की जरूरत होती है।

अहमदाबाद मंडल के पाँच रेल कर्मचारियों को संरक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में रेल परिचालन की संरक्षा के प्रति सतर्कता, सजगता एवं कर्तव्यनिष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने वाले पाँच कर्मचारियों को "संरक्षा पुरस्कार (Safety Award)" से सम्मानित किया गया।

दिनांक 24 अगस्त 2026 को आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने पाँचों कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इन कर्मचारियों ने ड्यूटी के दौरान संभावित संरक्षा संबंधी खामियों को समय रहते पहचानकर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की, जिससे संभावित दुर्घटनाओं एवं रेल परिचालन में व्यवधान को टाला जा सका।

वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी श्री अरविंद कुमार मीणा के अनुसार, सम्मानित कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

1. श्री अजयसिंह आर., लोको पायलट एवं श्री सुनील पटेल, सहायक लोको पायलट — विद्युत विभाग (ट्रेन परिचालन)

दिनांक 13 मई 2026 को श्री अजयसिंह आर., लोको पायलट एवं श्री सुनील पटेल, सहायक लोको पायलट को ट्रेन संख्या 14821 जोधपुर–साबरमती एक्सप्रेस में आबू रोड से साबरमती तक ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया था। ट्रेन आबू

रोड से 16:15 बजे रवाना हुई। सरतो रोड और इकबालगढ़ के बीच किलोमीटर संख्या 628/07–09 पर ट्रेन लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी। इसी दौरान चालक दल को ट्रेन में असामान्य झटका महसूस हुआ। दोनों कर्मचारियों ने स्थिति का तुरंत आकलन करते हुए संबंधित नियंत्रण कार्यालयों एवं स्टेशन अधिकारियों को इसकी सूचना दी तथा प्रभावित रेलखंड की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई की।

इकबालगढ़ स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दिए जाने के बाद प्रभावित स्थान से गुजरने वाली आगामी ट्रेनों को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की सावधानी गति के साथ संचालित करने की व्यवस्था की गई। दोनों कर्मचारियों की सतर्कता, सजगता एवं त्वरित कार्रवाई के कारण संभावित दुर्घटना को समय रहते टालने में महत्वपूर्ण मदद मिली तथा रेल परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित हुई।

2. श्री बंटी कुमार मीणा, सहायक लोको पायलट — विद्युत विभाग (ट्रेन परिचालन)

दिनांक 21 मई 2026 को श्री बंटी कुमार मीणा को वलसाड से अहमदाबाद तक ट्रेन संख्या 22186 के परिचालन के लिए नियुक्त किया गया था। ट्रेन 02:52 बजे रवाना होकर 03:45 बजे सूरत स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुँची। सूरत स्टेशन पर लोकोमोटिव की जांच के दौरान श्री बंटी कुमार मीणा ने पहिए संख्या 10 के ऊपर लगी द्वितीयक हेलिकल स्प्रिंग के टूटे होने का पता लगाया।

उन्होंने तत्काल लोको पायलट एवं स्टेशन अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद मुख्य लोको निरीक्षक श्री अशोक पाठक द्वारा लोकोमोटिव का निरीक्षण किया गया और 03:53 बजे लोकोमोटिव को खराब घोषित कर दिया गया। इसके बाद लोकोमोटिव संख्या 22540 को लगाया गया और ट्रेन को सुरक्षित रूप से अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया।

श्री बंटी कुमार मीणा की सतर्कता से लोकोमोटिव की गंभीर तकनीकी खराबी समय रहते सामने आई और संभावित दुर्घटना को टाला जा सका।

3. श्री सर्फराज, तकनीशियन ग्रेड-I — विद्युत विभाग

दिनांक 23 मई 2026 को श्री सर्फराज अहमदाबाद मंडल के साबरमती क्षेत्र में 16/24 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात थे। लोकोमोटिव संख्या 37162 की सामान्य जांच के दौरान वे बोगी कार्य क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पहिए संख्या 08 की टूटी हुई प्राथमिक हेलिकल स्प्रिंग का पता लगाया। उन्होंने तत्काल अपने शिफ्ट पर्यवेक्षक एवं संबंधित नियंत्रण कार्यालय को इसकी जानकारी दी।

बाद में खराब स्प्रिंग को बदल दिया गया। श्री सर्फराज द्वारा समय रहते खराबी की पहचान किए जाने से लोकोमोटिव को संभावित तकनीकी जोखिम से बचाया गया और रेल परिचालन की संरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।

4. श्री मेरा भाई, तकनीशियन ग्रेड-III — विद्युत विभाग (विद्युत कर्षण विभाग)

दिनांक 16 मई 2026 को श्री मेरा भाई विद्युत कर्षण डिपो में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। ड्यूटी के दौरान जखवाड़ा–बाकरोल रेलखंड के बीच ओवरहेड विद्युत उपकरण की पैदल गश्त करते समय उन्होंने ओवरहेड उपकरण के किलोमीटर संख्या 50/1 पर एक महत्वपूर्ण खराबी देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बिना इंसुलेटेड ओवरलैप वाले दो कैटेनरी तारों के बीच लगा जी-जम्पर टूटा हुआ था। यह खराबी समय रहते दूर नहीं की जाती तो ओवरहेड विद्युत आपूर्ति में गंभीर खराबी उत्पन्न हो सकती थी, जिससे ट्रेनों के परिचालन में व्यवधान तथा संरक्षा संबंधी जोखिम पैदा हो सकता था।

श्री मेरा भाई ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई। उनकी सतर्कता एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा से संभावित ओवरहेड उपकरण विफलता को समय रहते रोका जा सका।

रेल संरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

अहमदाबाद मंडल द्वारा रेल परिचालन की संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ड्यूटी के दौरान छोटी से छोटी असामान्यता को भी गंभीरता से पहचानना, उसकी तत्काल सूचना देना और समय पर आवश्यक कार्रवाई करना सुरक्षित रेल परिचालन का महत्वपूर्ण आधार है।

सम्मानित किए गए पाँचों कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता, सजगता, तकनीकी दक्षता एवं कर्तव्यनिष्ठा से यह साबित किया है कि कर्मचारियों की जागरूकता और त्वरित निर्णय क्षमता रेल संरक्षा को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भावनगर में 14 वर्षीय छात्रा के साथ रैगिंग का आरोप, 4 वरिष्ठ अधिकारियों और 2 प्रशासकों के खिलाफ आपराधिक मामले

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत के नए सिविल अस्पताल के एक होनहार युवक डॉ. हर्ष पंड्या की रैगिंग का शिकार होने के बाद आत्महत्या की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई है, ऐसे में भावनगर के कालियाबिड इलाके में सरदार पटेल स्कूल के पास माधव बॉयज हॉस्टल में पढ़ने वाले 14 वर्षीय कक्षा 9 के छात्र पर शारीरिक और मानसिक यातना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आने से अभिभावकों में फिर से दहशत फैल गई है।

पीड़ित के अभिभावक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, शिकायतकर्ता का 14 वर्षीय बेटा कक्षा 9 में पढ़ता है और माधव बॉयज़ हॉस्टल में रहता है। हॉस्टल में उसके साथ कमरा साझा करने वाले वरिष्ठ छात्र, जो NEET की तैयारी कर रहे थे, अक्सर उससे अपने काम करवाते थे। अगर वह काम करने से इनकार करता, तो वे उसे गाली देते, बार-बार पीटते और बाथरूम में फेंक देते थे। इतना ही नहीं, आरोपी छात्र उसे सिगरेट पीने के लिए मजबूर करते और यह कहकर ब्लैकमेल करते कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया, तो वे सबको बता देंगे कि वह सिगरेट पीता है। इसके अलावा, मुख्य सरगना कहे जाने वाले छात्र ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही, हॉस्टल के प्रभारी अंकुर और जिगर नाम के व्यक्ति भी उसे परेशान करते थे और उन्होंने 14 वर्षीय छात्र का सिगरेट पीते हुए वीडियो भी बनाया था।

जब पीड़ित छात्र को घर पर इस बारे में पता चला, तो उसके पिता ने छात्रावास के मालिक नीलेशभाई अहीर से सीसीटीवी फुटेज मांगी, और सीसीटीवी में वरिष्ठ छात्र स्पष्ट रूप से छात्र की मालिश करते, उसके सिर पर तेल डालते, उसे पीटते और उसे जबरदस्ती बाथरूम ले जाते हुए दिखाई दिए।

इस घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए, नीलमबाग पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर वरिष्ठ छात्रों और छात्रावास के अंकुर और जिगर के खिलाफ आईपीसी की धारा 115(2), 352, 351(3), 54 के तहत मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ 4 वरिष्ठ छात्रों और प्रशासकों को जब्त कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा गुजरात प्रतिनिधिमंडल की कनाडा यात्रा : दूसरा दिन

मुख्यमंत्री की टाई टोरंटो के उद्यमियों और कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीएचसीसी) के साथ राउंड टेबल बैठकें हुईं

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट-2027 के संदर्भ में यूएस-कनाडा के दौरे पर गए गुजरात प्रतिनिधिमंडल की टोरंटो यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को दो राउंड टेबल बैठकों का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन राउंड टेबल बैठकों की श्रृंखला में टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स के लगभग 30 प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की।

उन्होंने स्टार्टअप्स फाउंडर्स, उद्यमियों और टाई के सदस्यों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में ग्लोबली कॉम्पीटिटिव इनोवेशन, इकोनॉमी बनाने के भविष्य उन्मुख विजन के बारे में चर्चा-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने गुजरात देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है, इस संदर्भ में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, पब्लिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक के क्षेत्रों में कनाडाई उद्यमों और गुजरात के इन क्षेत्रों के उद्यमों के बीच सहयोग और भागीदारी को अधिक मजबूत करने के संबंध में चर्चाएँ कीं।

इतना ही नहीं; राज्य की मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज और वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं की भी जानकारी टाई मेंबर्स को दी। टाई टोरंटो की स्थापना वर्ष 2000 में हुई है और कनाडा सरकार तथा उद्योग जगत को विश्वभर के सफल कनाडाई उद्यमियों के साथ जोड़ने का सेतु रूपी कार्य करने का उद्देश्य टाई करता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हेल्थकेयर, बायोटेक, मीडिया, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे बहुविध क्षेत्रों के लोग टाई के मेंबर्स हैं। उद्यमी, निवेशक, विशेषज्ञ और उद्योग अग्रणी परस्पर जुड़कर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग के साथ कॉन्टेक्ट्स और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टाई के माध्यम से कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन सदस्यों के साथ चर्चा-परामर्श के दौरान आगामी वाइब्रेंट गुजरात समिट-2027 से पहले गुजरात में निवेश, इनोवेशन और स्केलिंग के लिए अवसर तलाशने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा; एक अन्य राउंड टेबल अंतर्गत कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ आयोजित बैठक में सीएचसीसी द्वारा वाइब्रेंट समिट-2027 में सहभागिता के लिए दिखाई गई उत्सुकता की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपेक्षा व्यक्त की कि इसके परिणामस्वरूप बी2बी जुड़ाव, निवेश और भागीदारी के जो नए मार्ग खुलेंगे, वे कनाडा-गुजरात के बीच आर्थिक संबंधों को अधिक मजबूत बनाएँगे। इस राउंड टेबल बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री टी. नटराजन, उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ममता वर्मा तथा गुजरात प्रतिनिधिमंडल के वरिष्ठ सचिव जुड़े।

मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके द्वारा एकतानगर में IRCTC बजट होटल के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा

वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने आज मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एकतानगर में निर्माणाधीन IRCTC बजट होटल का दौरा कर चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक श्री भडके ने होटल में किए जा रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता, पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए प्रस्तावित सुविधाओं तथा संरक्षा व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने तथा यात्रियों की सुविधा एवं संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

श्री भडके ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एकतानगर स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ऐसे में यहां उपलब्ध कराई जाने वाली आवासीय सुविधाएं पर्यटकों के लिए सुविधाजनक, गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि एकतानगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आने वाले पर्यटकों एवं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IRCTC बजट होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल को एकता दिवस के अवसर पर पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके शुरू होने से एकतानगर आने वाले पर्यटकों को सुविधाजनक एवं किफायती आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी।

वडोदरा मंडल द्वारा एकतानगर क्षेत्र में यात्री सुविधाओं के विस्तार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सूरत आरटीओ के सख्त नियमों से डीलर और सब-डीलर नाराज हैं और सरकार से नीतियों और नियमों की समीक्षा की मांग कर रहे हैं

(निर्भीक, निष्पक्ष एवं निष्पक्ष छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत. गुजरात राज्य में किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन अनिवार्य हो गया है। आंदोलन के बिना कोई समस्या हल नहीं होती और आंदोलन के बाद आंदोलनकारी केवल आंदोलन से संतुष्टि पाना चाहते हैं। समस्या की जड़ से उसका समाधान नहीं होता, चाहे वह गुजरात के किसानों का आंदोलन हो, युवा छात्रों का आंदोलन हो, NEET परीक्षा के लिए छात्रों का आंदोलन हो, मेडिकल कॉलेज के छात्रों का आंदोलन हो, आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन हो, व्यापारियों का आंदोलन हो, इन सभी लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और सरकार, जिला प्रतिनिधि कलेक्टर को याचिका सौंपकर संतुष्ट होना पड़ता है। और आंदोलनों के बाद भी उनकी समस्याएं हल नहीं होतीं। गरीब

कामगारों को भी अपनी आजीविका के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है और सड़कों पर उतरने और विरोध प्रदर्शन करने के बाद भी उनका शारीरिक शोषण जारी रहता है।

सूरत शहर में जब आरटीओ (सड़क यातायात कार्यालय) बदलता है, तो नई नीतियां और नियम तुरंत लागू हो जाते हैं।

सूरत में उन नीतियों और नियमों का पालन करना अनिवार्य क्यों है जो पूरे गुजरात राज्य में लागू नहीं हैं? सूरत के व्यापारी, डीलर और उप-डीलर अपने शोरूम में नए वाहनों का स्टॉक क्यों नहीं रख सकते? सूरत का आरटीओ उन व्यापारियों पर अनावश्यक प्रतिबंध क्यों लगा रहा है जो शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं? जब पूरे गुजरात राज्य में ड्रग्स, शराब, गांजा और अफीम जैसे अन्य जहरीले पदार्थ बिना किसी रोक-टोक के बेचे जा रहे हैं, तो सूरत का आरटीओ डीलरों और उप-डीलरों को अपने शोरूम में दोपहिया वाहन रखने से क्यों रोक रहा है? अगर सरकार के पास ऐसा कोई कानून या नियम है, तो सूरत शहर में ही इसके खिलाफ कानून कैसे हो सकता है, जबकि सूरत के बाहर के शहरों में डीलर और सब-डीलर अपने शोरूम में वाहनों का स्टॉक रखकर कारोबार कर रहे हैं? राज्य सरकार को सूरत शहर के डीलरों और सब-डीलरों की इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। सूरत शहर में लगभग 250 से 300 छोटे-बड़े सब-डीलर हैं। और जब वे वहां काम करते हैं, तो वे प्रति शोरूम दो या दो से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और शोरूम का प्रबंधन करके अपनी आजीविका कमाते हैं, तो सूरत आरटीओ को इसमें क्या परेशानी हो रही है?

महंगाई के इस दौर में डीलर और सब-डीलर एक ही कंपनी के वाहनों का कारोबार नहीं कर सकते, जिसके चलते डीलर और सब-डीलर, खासकर सब-डीलर, शोरूम में बहुउद्देशीय वाहन रखकर ही काम चला रहे हैं। सूरत आरटीओ उन्हें ऐसा करने से रोकने में कहां नाकाम हो रहा है? सरकार को इस मामले में सूरत आरटीओ से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और सरकार के उच्च अधिकारियों को आरटीओ के इस तरह के बेतुके व्यवहार और तौर-तरीकों की जांच करनी चाहिए।

'श्रावण उत्सव : सौराष्ट्र के मेलों में 195 सखी मंडल की बहनों के उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का आयोजन

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विभिन्न पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को वेग

गांधीनगर : श्रावण माह अर्थात शिवालयों में शिव आराधना तथा मेलों का महापर्व। इस अवधि के दौरान राज्य के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों, शक्तिपीठों, कृष्ण मंदिरों, तीर्थधामों तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। राज्य सरकार द्वारा 'श्रावण उत्सव' के रूप में राज्य के 6 जिलों में दिनांक 26/08/2026 से 7/09/2026 के दौरान सखी मंडल की बहनों को उनके उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए विशेष प्लेटफॉर्म दिया गया है। इस महोत्सव के दौरान विभिन्न मेलों तथा धार्मिक आयोजनों में सखी मंडल की बहनें अपने उत्पाद अधिक लोगों तक पहुँचा सकें; ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप सखी मंडलों की बहनों की आय में वृद्धि होगी तथा 'वोकल फॉर लोकल' और 'लखपति दीदी' अभियान को अधिक गति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य की महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर देश के विकास में अग्रसर बनी हैं।

ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लि. (GLPC) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत कार्यरत स्वयं-सहायता समूहों (सखी मंडलों) द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य उत्पादों, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, परंपरागत वस्त्रों, पूजन सामग्री, घर सजावट की वस्तुओं तथा अन्य स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेलों में स्टॉल का आवंटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सखी मंडल की बहनों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता के चेक का भी वितरण किया जाएगा।

राजकोट और घेला सोमनाथ में जिला प्रशासन द्वारा मेले की पुरजोर तैयारियाँ चल रही हैं। घेला सोमनाथ में कल से पाँच दिनों के लिए मेला शुरू होगा। वहीं राजकोट में दिनांक 2 से 6 सितंबर तक रेसकोर्स में मेला आयोजित होने जा रहा है।

राजकोट में आयोजित मेले में सखी मंडलों की बहनों को 40 स्टॉल तथा घेला सोमनाथ में 15 स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा; पोरबंदर के मेले में 65 स्टॉल, गिर सोमनाथ में 20 स्टॉल, देवभूमि द्वारका में 20 स्टॉल आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा; भावनगर में निष्कलंक महादेव के मेले में 20 स्टॉल तथा नर्मदा जिले में नीलकंठधाम, पोइचा में भी 15 स्टॉल आवंटित किए जाएंगे।

गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लि. द्वारा सखी मंडल की बहनों को निःशुल्क स्टॉल के अलावा उनके रहने और भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा; सखी मंडल की बहनों को आने-जाने का किराया भी दिया जाता है। इस प्रकार सखी मंडल की बहनें बिना किसी अन्य खर्च के अपने सामान की अच्छी तरह बिक्री कर सकती हैं।

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें; इसके लिए उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हैंडीक्राफ्ट की वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक साधन सहायता के लिए बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ अब अपने घर-परिवार के गुजारे में सहभागिता के साथ 'लखपति दीदी' बनकर राज्य और देश के आर्थिक विकास में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर रही हैं।

खिजडिया पक्षी अभयारण्य गुजरात में ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के प्रजनन के लिए प्रमुख स्थल बना; नए शोध में रोचक तथ्य सामने आए

अध्ययन में यह भी पता चला कि ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क पक्षी अपने बच्चों की बहुत देखभाल करता है। 89 अवलोकनों में पाया गया कि घोंसले में आने के दौरान वयस्क ब्लैक-नेक्ड-स्टॉर्क औसतन 62 मिनट तक घोंसले में मौजूद रहे

गांधीनगर, 25 अगस्त : गुजरात वन विभाग के अधीनस्थ स्वायत्त संस्था गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (जीईईआर यानी गीर) फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जामनगर जिले में स्थित खिजडिया पक्षी अभयारण्य में ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क (Ephippiorhynchus asiaticus) पक्षी के बारे में अध्ययन किया। इस अध्ययन में पता चला कि खिजडिया पक्षी अभयारण्य ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क (काली गर्दन वाले सारस) के लिए अत्यंत अनुकूल प्रजनन स्थल है। ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क भारत के सबसे बड़े तथा विशिष्ट जलपक्षियों में से एक है।

इस अध्ययन में ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क पक्षी की प्रजनन की उल्लेखनीय सफलता देखने को मिली। निरीक्षण अंतर्गत लाए गए चारों घोंसलों से बच्चे सफलतापूर्वक बाहर आए। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि रामसर साइट के रूप में घोषित खिजडिया पक्षी अभयारण्य ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क पक्षी के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

पीयर-रिव्यूड अंतरराष्ट्रीय जर्नल Journal of Threatened Taxa में प्रकाशित इस अध्ययन में जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान खिजडिया पक्षी अभयारण्य में ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क की आबादी की स्थिति, प्रजनन पारिस्थितिकी (ब्रीडिंग इकोलॉजी), घोंसले के स्थानों की विशेषताओं और प्रजनन क्षमता का मूल्यांकन किया गया। यह शोध गीर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों संदीप मुंजपरा, दिव्यराजसिंह जाडेजा, नीता सोलंकी, अमितकुमार नायक और बी. पी. पति द्वारा किया गया।

वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, "गीर फाउंडेशन की पूरी शोध टीम को मैं बधाई देता हूँ। इस अध्ययन ने ब्लैक-नेक्ड सारस पक्षी के अद्भुत व्यवहार एवं प्रजनन पारिस्थितिकी पर नया प्रकाश डाला है। इन निष्कर्षों के आधार पर हम इस पक्षी के संरक्षण के बारे में प्रभावी कदम उठा सकेंगे।"

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री प्रवीण माळी ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खिजडिया पक्षी अभयारण्य सहित राज्य की अमूल्य प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए हैं।"

अध्ययन में ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के प्रजनन के बारे में नई जानकारी मिली

ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क अपनी कम संख्या में पाई जाने वाली प्रजनन आबादी के लिए जाना जाता है। गुजरात में खिजडिया पक्षी अभयारण्य और इसके आसपास का क्षेत्र लंबे समय से इस पक्षी के लिए महत्वपूर्ण

आवास के रूप में पहचाना जाता है। हालाँकि, इसके प्रजनन के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी उपलब्ध है।

गीर फाउंडेशन के निदेशक श्री बी. पी. पति (आईएफएस) ने कहा, "शोधकर्ताओं ने अभयारण्य के आठ मैनेजमेंट जोन में फैले 48 जियोरेफरेंस्ड सैंपलिंग प्वाइंट का उपयोग करके व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण किया। अध्ययन में घोंसले का निरीक्षण, व्यवहार का अवलोकन और इसके आवास का मूल्यांकन किया गया। इस दौरान 320 घंटे से अधिक के अवलोकन के आँकड़े एकत्र किए गए।"

श्री बी. पी. पति ने आगे कहा, "अध्ययन में सबसे उल्लेखनीय बात यह सामने आई कि अध्ययन अंतर्गत ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के चार सक्रिय घोंसलों में प्रत्येक घोंसले में एक प्रजनन जोड़ी थी और प्रत्येक जोड़ी ने सफलतापूर्वक दो बच्चों का पालन-पोषण किया था। इस प्रकार, चार घोंसलों में कुल आठ बच्चे दर्ज हुए। इसके अलावा, नियमित रूप से दिखाई देने वाले पाँच गैर-प्रजनन वयस्क पक्षियों सहित अध्ययन अवधि के दौरान अभयारण्य में इस पक्षी की संख्या 21 से अधिक दर्ज की गई थी।"

शोध में पता चला कि ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के चारों घोंसले बबूल के पेड़ पर बनाए गए थे। ये घोंसले जमीन से तीन से 4.5 मीटर की ऊँचाई पर थे। सामान्यतः ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क बबूल तथा बरगद-पीपल जैसे बड़े आकार की स्थानीय वृक्ष प्रजातियों पर घोंसले बनाते हैं। हालाँकि, इस अध्ययन में पता चला कि जहाँ स्थानीय स्तर पर घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त वृक्षों की उपलब्धता कम होती है, वहाँ यह पक्षी बबूल जैसे पेड़ों पर भी घोंसले बनाता है।

ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के लिए खिजडिया बहुत महत्वपूर्ण स्थल बना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. जयपाल सिंह ने कहा, "यह शोध ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क के आवास के पारिस्थितिक महत्व को भी और मजबूत बनाता है। ब्लैक-नेक्ड स्टॉर्क को जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए केवल पानी पर्याप्त नहीं है। इसके सफल प्रजनन के लिए उपयुक्त भोजन प्राप्त करने वाले क्षेत्र, जलीय शिकार, घोंसला बनाने योग्य पेड़, उथला पानी, वनस्पति और अपेक्षाकृत कम मानवीय हस्तक्षेप वाले क्षेत्र आवश्यक हैं।" डॉ. जयपाल सिंह ने जोड़ा, "चारों घोंसलों के स्थानों की विशेषताएँ - विशेष रूप से उथला पानी, जल सतह के ऊपर की वनस्पति, ऊँचे स्थान और कम व्यवधान - आवास प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। इन परिस्थितियों को बनाए रखना खिजडिया में इस प्रजाति की प्रजनन आबादी को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।"

गीर फाउंडेशन के उप निदेशक अमितकुमार नायक ने कहा, "घोंसलों के सभी स्थानों में कुछ सामान्य पारिस्थितिक विशेषताएँ देखने को मिलीं। सभी घोंसले 0.3 से 0.7 मीटर की गहराई वाले उथले पानी वाले क्षेत्रों के पास थे और उनके आसपास खुला पानी, जल सतह के ऊपर की वनस्पति तथा ऊँचा क्षेत्र था। ये परिस्थितियाँ मछली, उभयचर, क्रस्टेशियन और जलीय अकशेरुकी जीवों सहित पर्याप्त भोजन स्रोत उपलब्ध कराती हैं, जो प्रजनन करने वाले पक्षियों और बढ़ते बच्चों के लिए आवश्यक हैं।"

शोधकर्ताओं ने नोट किया कि अगस्त और सितंबर में इस पक्षी के व्यवहार में बदलाव के साथ प्रजनन गतिविधि शुरू हुई और इसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में घोंसला बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत के दौरान अंडों से बच्चे बाहर आए थे, जबकि दिसंबर तक बच्चों के पालन-पोषण की गहन प्रक्रिया जारी रही थी। वर्ष के अंत तक बच्चे घोंसले से बाहर निकल गए और प्रजनन चक्र पूरा हो गया।

यह पक्षी माता-पिता के रूप में मजबूत जिम्मेदारी निभाता है

गीर फाउंडेशन के वैज्ञानिक तथा अध्ययन के एक लेखक डॉ. संदीप मुंजपरा ने कहा, "अध्ययन में इस प्रजाति द्वारा दरशाई जाने वाली मजबूत पितृत्व की जिम्मेदारी देखने को मिली। इस पक्षी के 89 निरीक्षण और दौरों के दौरान हमने दर्ज किया कि वयस्क स्टॉर्क औसतन 62 मिनट तक घोंसले में मौजूद रहे। भोजन प्राप्त करने के लिए दर्ज की गई 94 प्रतिशत उड़ानों में एक माता-पिता पक्षी ने घोंसले पर दूसरे पक्षी का स्थान लिया। यह बात माता-पिता द्वारा बेहद समन्वित ढंग से बच्चों की देखभाल किए जाने को दर्शाती है। ऐसे व्यवहार से अंडों और बच्चों की लगातार सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित होती है।"

महत्वपूर्ण बात यह है कि घोंसलों के निरीक्षण की अवधि के दौरान शोधकर्ताओं ने घोंसला छोड़ने, शिकारी जानवरों द्वारा हमला किए जाने या बच्चों की मृत्यु की एक भी घटना दर्ज नहीं की। चारों घोंसलों से बच्चे सफलतापूर्वक बाहर निकले, जिसके परिणामस्वरूप 100 प्रतिशत फ्लेजिंग सफलता दर दर्ज की गई। अध्ययन के अनुसार इतनी अधिक प्रजनन सफलता भारत के अन्य क्षेत्रों में किए गए अवलोकनों की तुलना में उल्लेखनीय है। यहाँ घोंसले से बच्चों के सफलतापूर्वक बाहर निकलने का अनुपात अधिक देखा गया है।

घोंसले से बाहर आने के बाद के अवलोकनों में पता चला कि स्टॉर्क के बच्चे घोंसला छोड़ने के बाद अपने माता-पिता पर निर्भर रहते थे। भोजन के लिए कई बार अनुरोध और माता-पिता द्वारा बच्चों के साथ भोजन साझा करने की घटनाएँ शोधकर्ताओं ने दर्ज कीं। यह लंबे समय तक माता-पिता की देखभाल और स्वतंत्र रूप से भोजन प्राप्त करने की क्षमता के क्रमशः विकास की ओर संकेत करता है।

वन विभाग के संरक्षण प्रयास सफल हो रहे हैं

अभयारण्य में अपेक्षाकृत स्थिर जल परिस्थितियाँ, प्रचुर मात्रा में शिकार/भोजन की उपलब्धता और मानवीय हस्तक्षेप का कम स्तर इस प्रजनन सफलता में महत्वपूर्ण कारक माने जाते हैं। घोंसले प्रतिबंधित क्षेत्रों में थे, जहाँ पानी वाले क्षेत्रों तथा पेड़ों से आच्छादित क्षेत्रों के बीच की सीमा तथा ऊँचे टीले जैसे भू-भाग थे। इन क्षेत्रों में बाढ़ का जोखिम कम रहता है और निकट के भोजन प्राप्त करने वाले क्षेत्रों तक आसानी से पहुँचा जा सकता है।

एक राखी देश के जवानों के नाम

गुजरात की आँगनबाड़ी की बहनों ने सीमा के जवानों की रक्षा के लिए 4.50 लाख से अधिक राखियाँ भेजीं

भारतीय सेना, एयर फोर्स, नेवी, बीएसएफ और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को राखियाँ सौंपी गईं

गांधीनगर : रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के उपलक्ष्य में देश की सीमाओं पर तत्परता से रात-दिन ड्यूटी करने वाले वीर जवानों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्नेह की भावना व्यक्त करने के लिए आँगनबाड़ी की बहनों द्वारा रक्षा के प्रतीक के रूप में 4.50 लाख राखियाँ जवानों को भेजी गई हैं। उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में मंगलवार को रक्षासूत्र कलश सीमावर्ती बलों के अधिकारियों को प्रतीक रूप में अर्पित किया गया।

सीमा पर तैनात जवान अपने परिवार से दूर रहकर मातृभूमि की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। उनकी सदैव रक्षा की भावना

के साथ महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री डॉ. मनीषाबेन वकील के मार्गदर्शन में आँगनबाड़ी बहनों ने रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में ये राखियाँ भेजी हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और घर-परिवार से दूर रहने वाले सेना के जवानों की रक्षा के लिए आँगनबाड़ी बहनों ने यह रक्षासूत्र बनाया है।

भाई-बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन ये सैनिक सीमा पर रहकर भी मना सकें और माताएँ-बहनें उनके साथ जुड़ी हुई हैं; ऐसा अहसास उन्हें कराने का सराहनीय प्रयास "एक राखी देश के जवानों के नाम" अंतर्गत गुजरात पिछले तीन वर्षों से कर रहा है।

गुजरात की बहनों ने वीर जवानों की रक्षा का कवच राखियों के माध्यम से प्रदान कर भाई-बहन के प्रेम के त्योहार को राष्ट्रभक्तिमय बनाया है। इस रक्षासूत्र कलश को आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ के गांधीनगर स्थित जवानों ने स्वीकार किया।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास सचिव श्री राकेश शंकर, महिला एवं बाल विकास आयुक्त डॉ. रणजीत कुमार सिंह, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ के जवान, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें आदि उपस्थित रहे।

पहले घंटे में ही छाया सुमैक्स इंजीनियरिंग का आईपीओ, निवेशकों ने जमकर लगाई बोली

नई दिल्ली। ऑटो रिफिनिश मार्केट के लिए ऑटोमोटिव ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सुमैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड का 53.40 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलते ही निवेशकों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। इश्यू को शुरुआती घंटों में ही जोरदार प्रतिक्रिया मिली और पहले घंटे के भीतर यह पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया। दोपहर 2:45 बजे तक आईपीओ को कुल 2.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। कंपनी के इस इश्यू में निवेशक 28 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। इश्यू बंद होने के बाद 31 अगस्त को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि सफल निवेशकों के डीमैट खातों में शेयर 1 सितंबर को क्रेडिट होने की संभावना है। कंपनी के शेयर 2 सितंबर को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध हो सकते हैं।

सुमैक्स इंजीनियरिंग ने अपने आईपीओ के लिए 95 रुपये से 101 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। इस इश्यू का लॉट साइज 1,200 शेयर है। यानी एक लॉट के लिए निवेशकों को न्यूनतम 1,14,000 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं रिटेल निवेशकों को न्यूनतम दो लॉट के लिए बोली लगानी होगी। इस हिसाब से रिटेल निवेशक को 2,400 शेयरों के लिए 2,42,400 रुपये तक का निवेश करना होगा, अगर वह ऊपरी प्राइस बैंड 101 रुपये प्रति शेयर पर बोली लगाता है। आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 52,87,200 शेयर बाजार में पेश किए जा रहे हैं। इनमें करीब 42,91,200 नए शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिनसे लगभग 44 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। इसके अलावा करीब 9,96,000 शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से पेश किए जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। इश्यू में निवेशकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए भी शेयरों का निर्धारित हिस्सा रखा गया है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी क्यूआईबी के लिए करीब 49.90 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित है। रिटेल निवेशकों के लिए 35.04 प्रतिशत और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स यानी एनआईआई के लिए 15.06 प्रतिशत हिस्सा रखा गया है। रिटेल निवेशकों के लिए निर्धारित हिस्से में मार्केट मेकर के लिए 5.04 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। इश्यू के लिए जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी दी गई है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मार्केट मेकर हैं।

आईपीओ को मिले शुरुआती रिस्पॉन्स के पीछे कंपनी के मजबूत होते वित्तीय प्रदर्शन को भी एक अहम वजह माना जा रहा है। कंपनी की ओर से बाजार नियामक सेबी के पास जमा किए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वित्त वर्षों में कंपनी के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ 7.43 करोड़ रुपये रहा था। इसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 9.98 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 12.76 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। यानी तीन वित्त वर्षों के दौरान कंपनी के मुनाफे में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।

कंपनी के कारोबार से होने वाले राजस्व में भी इस अवधि में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में सुमैक्स इंजीनियरिंग को 131.54 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ था। अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 147.18 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कुल राजस्व 148.34 करोड़ रुपये रहा। हालांकि राजस्व में बढ़ोतरी की रफ्तार मुनाफे की तुलना में कुछ धीमी रही, लेकिन कंपनी ने इस अवधि में अपने लाभ को लगातार मजबूत करने में सफलता हासिल की है। निवेशकों की नजर अब इस बात पर भी रहेगी कि लिस्टिंग के बाद कंपनी अपने कारोबार की इस रफ्तार को कितनी मजबूती से बनाए रख पाती है।

कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक दूसरा पहलू उसका कर्ज भी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में कंपनी पर 6.43 करोड़ रुपये का कर्ज था। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 7.75 करोड़ रुपये हो गया और वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का कर्ज बढ़कर 13.06 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यानी कंपनी के कर्ज में पिछले तीन वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में निवेशकों के लिए कंपनी के बढ़ते मुनाफे के साथ-साथ कर्ज की स्थिति पर नजर रखना भी महत्वपूर्ण होगा।

आपकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने 500 नए अत्याधुनिक '112-जनरक्षक' वाहनों को फ्लैग ऑफ कर प्रस्थान कराया

समग्र गुजरात में 24 घंटे कुल 1,000 'जनरक्षक' वाहन इमर्जेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैनात

गांधीनगर : राज्य के नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी इमर्जेंसी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गुजरात पुलिस के बेड़े में और 500 अत्याधुनिक '112-जनरक्षक' वाहनों को शामिल किया गया है। मंगलवार को नवा सचिवालय, गांधीनगर से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने इन नए वाहनों को फ्लैग ऑफ कर प्रस्थान कराया। इन नए 500 वाहनों के जुड़ने के साथ अब समग्र गुजरात में 24 घंटे कुल 1,000 'जनरक्षक' वाहन इमर्जेंसी रिस्पॉन्स के लिए तैनात रहेंगे।

आधुनिक 150 सीटों वाले कॉल सेंटर, कम्प्यूटर एडेड डिस्पैच (सीएडी) सिस्टम और कॉलर लोकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से राज्य का औसत पुलिस रिस्पॉन्स टाइम घटकर केवल 10 मिनट 49 सेकंड हुआ है। नए वाहनों तथा आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस रिस्पॉन्स टाइम को 8 मिनट से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। ओला, उबर, रैपिडो और भारत टैक्सी जैसी

ऐप्स में भी 112 पैनिक बटन का इंटीग्रेशन किया गया है।

फ्लैग ऑफ के अवसर पर राज्य मंत्री श्री कमलेश पटेल ने कहा कि गुजरात शांति, समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में देश का अग्रणी राज्य रहा है। गुजरात पुलिस हमेशा जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। 112-इमर्जेंसी सेवा के माध्यम से सहायता और अधिक तेज एवं प्रभावी बनेगी। अब जब कोई भी नागरिक 112 नंबर पर डायल करेगा, तब यथासंभव कम समय में पुलिस सहायता पहुँचे; इस दिशा में यह सेवा और अधिक सक्षम बनेगी।

जनरक्षक प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के केवल 11 माह की अल्पावधि में 11.04 लाख से अधिक इमर्जेंसी कॉल में समन्वित सेवाएँ प्रदान की गई हैं, जबकि 6.74 लाख से अधिक पुलिस इमर्जेंसी घटनाओं में तत्काल सेवा प्रदान की गई है।

500 नए अत्याधुनिक जनरक्षक वाहनों के शामिल होने से गुजरात की 112 इमर्जेंसी सेवा अधिक तेज, तकनीक आधारित एवं नागरिक-केंद्रित बनेगी।

इस अवसर पर राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुणकुमार सोलंकी, सीआईडी क्राइम डीजीपी डॉ. के. एल. एन. राव, लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी श्री राजकुमार पांडियन, पुलिस ट्रेनिंग डीजीपी श्री नीरजा गोटरू, प्रधान सचिव श्री निपुणा तोरवणे, पी एंड एम एडीजीपी श्री खुरशीद अहमद सहित उच्च पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

अहमदाबाद मंडल द्वारा ट्रेनों में सघन पेस्ट एवं रोडेंट कंट्रोल अभियान शुरू,मानसून के दौरान ट्रेनों में सफाई एवं हाइजिन व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में विशेष पहल

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ट्रेनों में पेस्ट एवं रोडेंट कंट्रोल (PRC) अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस सहित अहमदाबाद मंडल की अन्य यात्री ट्रेनों में भी निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान किया जा रहा है। इसी क्रम में ट्रेन संख्या 12957 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में यह विशेष अभियान 23 अगस्त 2026 से शुरू किया गया है।

मानसून के दौरान कॉकरोच, चूहे एवं अन्य कीटों की समस्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए यह अभियान साबरमती स्थित इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो में ट्रेन के निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ट्रेन में कॉकरोच, चूहे एवं अन्य कीटों की समस्या को शुरुआती स्तर पर ही कंट्रोल करना तथा यात्रियों के लिए साफ-सुथरा एवं हाइजिन वाला वातावरण सुनिश्चित करना है।

संभावित कीट प्रभावित स्थानों पर विशेष कंट्रोल उपाय

अभियान के तहत ट्रेन के प्रत्येक कोच का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। कोच में ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है,

जहां कॉकरोच या अन्य कीट छिप सकते हैं अथवा उनके पनपने की संभावना हो सकती है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार स्पेशल ट्रीटमेंट एवं स्प्रे किया जा रहा है। इस कार्य के लिए निर्धारित मानकों एवं सेफ्टी प्रोसीजर्स के अनुसार टेम्प्रिड एससी इंसक्टिसाइड स्प्रे का उपयोग किया जा रहा है।

अभियान के दौरान ट्रीटमेंट किए गए स्थानों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तथा आवश्यकता पड़ने पर री-ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, ताकि ट्रेनों में लंबे समय तक प्रभावी पेस्ट कंट्रोल सुनिश्चित किया जा सके।

अहमदाबाद मंडल की अन्य यात्री ट्रेनों में भी पेस्ट एवं रोडेंट कंट्रोल की गतिविधियां नियमित रूप से की जा रही हैं। निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान ट्रेनों में इंस्पेक्शन, ट्रीटमेंट एवं मॉनिटरिंग के माध्यम से कीट एवं चूहों की संभावित समस्या को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

यात्रियों की सुविधा एवं हाइजिन पर विशेष ध्यान

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा:

"ट्रेनों में यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मानसून के दौरान कॉकरोच, चूहे एवं अन्य कीटों की समस्या को रोकने के लिए विशेष मॉनिटरिंग और समय पर कंट्रोल मेजर्स करना आवश्यक है। स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में शुरू किया गया यह विशेष पीआरसी अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रिवेंटिव इनिशिएटिव है। हमारा प्रयास है कि ट्रेन के निर्धारित मेंटेनेंस के दौरान सफाई एवं हाइजिन से संबंधित सभी निर्धारित स्टैंडर्ड्स का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार अन्य यात्री ट्रेनों में भी पेस्ट एवं रोडेंट कंट्रोल की गतिविधियों को प्रभावी रूप से जारी रखा जा रहा है, ताकि यात्रियों को साफ-सुथरा एवं बेहतर यात्रा अनुभव मिल सके।"

अहमदाबाद मंडल यात्रियों के लिए ट्रेनों में क्लीन, सेफ एवं कम्फर्टेबल ट्रैवल एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

यात्रियों को स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु भावनगर मंडल में खानपान इकाइयों का गहन जांच अभियान

रेलवे बोर्ड एवं पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM-WR) श्री तरूण जैन के निर्देशानुसार रेल यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों में सभी खानपान इकाइयों का गहन स्वच्छता निरीक्षण एवं विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भावनगर मंडल में संचालित सभी खानपान इकाइयों पर भी गहन स्वच्छता निरीक्षण एवं विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के दिशा-निर्देशन में वाणिज्य एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा खानपान इकाइयों में स्वच्छता, खाद्य गुणवत्ता तथा आवश्यक दस्तावेजों की नियमित जांच की जा रही है।

इसी अभियान के तहत 24 अगस्त 2026 को भावनगर परा स्थित खानपान इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाणिज्य निरीक्षक एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा टी एंड रिफ्रेशमेंट स्टॉल के वेंडर के पास वैध चिकित्सा

प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं पाया गया।

यात्रियों के स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस अनियमितता के मद्देनजर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशानुसार भावनगर परा स्थित उक्त खानपान इकाई को बंद करा दिया गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर मंडल के सभी खानपान इकाई संचालकों एवं वेंडरों से अपील की है कि वे रेलवे द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं मानकों का कड़ाई से पालन करें। खानपान इकाइयों में स्वच्छता बनाए रखने के साथ-साथ सभी आवश्यक दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्र वैध एवं अद्यतन रखें।

उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों के स्वास्थ्य एवं सुविधा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा यात्रियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप स्वच्छ, सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सभी खानपान इकाई संचालकों एवं वेंडरों की जिम्मेदारी है।

भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधा एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के निरीक्षण एवं जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

रात की देखभाल से निखरेगी त्वचा, देसी नुस्खों के साथ अपनाएं आसान नाइट स्किनकेयर रूटीन

दिनभर धूप, धूल, प्रदूषण और तनाव का सामना करने के बाद हमारी त्वचा को रात के समय आराम और देखभाल की जरूरत होती है। जब हम सोते हैं, तब शरीर के साथ त्वचा भी अपने स्तर पर रिकवरी की प्रक्रिया में रहती है। रात के समय त्वचा की देखभाल के लिए सही आदतें अपनाने से उसे नमी बनाए रखने, रूखेपन को कम करने और सुबह चेहरे को तरोताजा महसूस कराने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि स्किनकेयर में रात की दिनचर्या को विशेष महत्व दिया जाता है। इसे आम बोलचाल में 'ब्यूटी स्लीप' भी कहा जाता है, क्योंकि पर्याप्त नींद के दौरान शरीर को आराम मिलता है और त्वचा की प्राकृतिक प्रक्रियाएं बेहतर तरीके से चलती हैं। भारतीय घरों में पीढ़ियों से कई प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। कच्चा दूध, मलाई, हल्दी और नारियल या बादाम जैसे तेल घरेलू सौंदर्य देखभाल का हिस्सा रहे हैं। हालांकि हर प्राकृतिक चीज हर व्यक्ति की त्वचा के लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी घरेलू नुस्खे को चेहरे पर लगाने से पहले अपनी त्वचा की प्रकृति और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना जरूरी है। खासकर संवेदनशील त्वचा, एलर्जी या किसी त्वचा संबंधी समस्या की स्थिति में विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है।

रात की देसी स्किनकेयर रूटीन में सबसे पहला कदम चेहरे की अच्छी तरह सफाई होना चाहिए। दिनभर चेहरे पर धूल, पसीना, प्रदूषण, सनस्क्रीन और मेकअप की परत जमा हो सकती है। ऐसे में सोने से पहले चेहरे को साफ करना बेहद जरूरी है। पारंपरिक घरेलू देखभाल में कच्चे दूध का इस्तेमाल त्वचा की सफाई के लिए किया जाता रहा है। दूध में लैक्टिक एसिड और वसा मौजूद होती है, जो त्वचा को मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकती है।

यदि कच्चा दूध इस्तेमाल करना हो तो दो चम्मच दूध लेकर उसमें कॉटन पैड या कॉटन बॉल भिगोकर चेहरे और गर्दन पर बहुत हल्के हाथों से लगाया जा सकता है। इसके बाद चेहरे को साफ पानी से धो लेना चाहिए। हालांकि कच्चे दूध के बजाय त्वचा के अनुरूप किसी सौम्य फेस क्लींजर का इस्तेमाल अधिक सुरक्षित और व्यावहारिक विकल्प हो सकता है, खासकर यदि त्वचा संवेदनशील हो या मुंहासों की समस्या रहती हो। किसी भी घरेलू सामग्री को पहली बार चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना समझदारी है।

त्वचा की देखभाल से जुड़े घरेलू उपायों में नाभि में तेल लगाने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है। कुछ लोग रात को सोने से पहले नाभि के आसपास नारियल, सरसों या बादाम का तेल लगाते हैं और इसे त्वचा की नमी तथा शरीर की अन्य समस्याओं से जोड़कर देखते हैं। हालांकि नाभि में तेल लगाने से चेहरे की चमक बढ़ने या पीरियड क्रैम्प्स जैसी समस्याओं का समाधान होने के दावों के पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं। इसलिए इसे पारंपरिक घरेलू आदत के रूप में ही देखा जाना चाहिए, किसी बीमारी का उपचार मानकर नहीं।

यदि त्वचा पर तेल लगाना पसंद है तो चेहरे के लिए उपयुक्त मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल अधिक प्रभावी और नियंत्रित तरीका हो सकता है। बहुत शुष्क त्वचा वाले लोग डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ की सलाह से उपयुक्त फेस ऑयल या मॉइश्चराइजर चुन सकते हैं। वहीं तैलीय या मुंहासे वाली त्वचा पर भारी तेल लगाने से कुछ लोगों में परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए त्वचा की जरूरत के अनुसार उत्पाद चुनना जरूरी है।

होंठों की देखभाल भी रात की स्किनकेयर रूटीन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिनभर धूप, हवा और कम पानी पीने की वजह से होंठ सूखे और फटे हुए महसूस हो सकते हैं। घरेलू सौंदर्य देखभाल में मलाई और हल्दी का इस्तेमाल होंठों की देखभाल के लिए किया जाता रहा है। मलाई त्वचा को मुलायम बनाने वाली नमी प्रदान कर सकती है, जबकि हल्दी को पारंपरिक रूप से त्वचा की देखभाल में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन होंठों पर हल्दी लगाने से कालापन निश्चित रूप से दूर होगा या होंठ गुलाबी हो जाएंगे, ऐसा दावा वैज्ञानिक रूप से स्थापित नहीं है।

होंठों के लिए रात में किसी अच्छे मॉइश्चराइजिंग लिप बाम या पेट्रोलियम जेली जैसी सुरक्षित मॉइश्चराइजिंग सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई घरेलू उपाय आजमाना हो तो पहले थोड़ी मात्रा लगाकर यह देखना जरूरी है कि जलन या एलर्जी तो नहीं हो रही। होंठों पर नींबू, बेकिंग सोडा या तेज रगड़ जैसे उपायों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे संवेदनशील त्वचा को नुकसान हो सकता है।

रात की स्किनकेयर में नाइट क्रीम का भी अपना महत्व है। दिन में त्वचा को धूप और प्रदूषण से बचाने के लिए जहां सनस्क्रीन महत्वपूर्ण होता है, वहीं रात में त्वचा को मॉइश्चराइज करने के लिए अच्छी क्रीम उपयोगी हो सकती है। रात में चेहरा साफ करने के बाद अपनी त्वचा के अनुरूप मॉइश्चराइजर या नाइट क्रीम लगाई जा सकती है। इसे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाया जाए। आंखों के बेहद करीब या पलकों पर सामान्य फेस क्रीम लगाने से बचना चाहिए, जब तक उत्पाद विशेष रूप से उस क्षेत्र के लिए न बना हो।

नाइट क्रीम चुनते समय त्वचा की जरूरत को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य या शुष्क त्वचा के लिए हाइड्रेटिंग सामग्री वाली क्रीम उपयोगी हो सकती है। तैलीय और मुंहासे वाली त्वचा के लिए हल्की, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्रीम बेहतर विकल्प हो सकती है। एंटीऑक्सीडेंट और कुछ विटामिन युक्त उत्पाद भी स्किनकेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन किसी भी सक्रिय सामग्री का उपयोग त्वचा की जरूरत और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार करना चाहिए।